04 - मानवाधिकार संरक्षण का नया रोडमैप तैयार करने...

05 - शिक्षा, संस्कृति एवं भारत बोध के समागम की पहल

A Daily News Magazine

भोपाल

शुक्रवार, 10 जनवरी, 2025

06 - प्रदेश के कई जिलों में आज कोल्ड-डे का अलर्ट

07 - हाईकोर्ट ने थानों से मंदिर हटाने वाली याचिका की खारिज

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष -22 अंक-131 नगर संस्करण, पृष्ठ -8, मूल्य रू.- 2 (डाक पंजीयन संख्याः म.प्र./भोपाल/4-391/2018-20)

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

सुरक्षा के लिहाज से बांग्लादेश क्यों बन रहा भारत के लिए खतरा

जनरल मनोज नरवणे (रि)

बांग्लादेश और भारत के बीच सहयोग और तनाव का एक लंबा और जटिल इतिहास रहा है। इतने वर्षों में, यह रिश्ता राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी पहलुओं के साथ विकसित होता रहा है। दोनों देश व्यापार, इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों के अलावा जल संपदा की साझीदारी समेत दूसरे मामलों में भी आपसी सहयोग बढ़ाते गए हैं, लेकिन बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन और हिंसा के साथ शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट और पिछले अगस्त में देश से हसीना का पलायन पिछले साल की बड़ी घटनाओं में शुमार हैं। इसने दोनों देशों के आपसी रिश्ते का स्वरूप बदल दिया और भारत के लिए सुरक्षा संबंधी गंभीर संकट पैदा कर दिया, जिसकी सीधी वजह बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन ही है।

यह सत्ता परिवर्तन जनता का भरोसा गंवा चुकी सरकार के खिलाफ दो से ज्यादा साल से मजबूत होते जा रहे आंदोलन का नतीजा है। अवामी लीग विरोधी भावनाएं कितनी उग्र हो चुकी थीं इसका अंदाज़ा इस पार्टी और इसके संस्थापक शेख मुजीबुर्रहमान से जुड़ी हर चीज के प्रति लोगों की नफरत से लगाया जा सकता है। जिस शख्स को राष्ट्रपिता माना जाता था उनकी जबरदस्त निंदा की जा रही थी और उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही थीं। वर्षों के दमन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। हसीना सरकार से जुड़ाव और उसका समर्थन करने के कारण बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं हावी हो गई थीं और उसे इस गुस्से का नुकसान उठाना पड़ा। भारत में हसीना का टिके रहना भी भारत के खिलाफ इस गुस्से को भड़का रहा है।

मुख्य सलाहकार के रूप में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में विभिन्न मंत्रियों वाली वर्तमान सत्ता खुद को मजबूत बनाने के लिए भारत विरोधी भावना का इस्तेमाल कर रही है। यह बदला हुआ नजरिया सुरक्षा संबंधी सरोकारों, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता संबंधी द्विपक्षीय रिश्ते के तमाम पहलुओं को प्रभावित कर रहा है। बांग्लादेश की नई सरकार ने जो राजनीतिक दिशा पकड़ी है उसका भारत के कूटनीतिक पहलू पर अहम प्रभाव पड़ेगा। भारत ने हसीना के नेतृत्व वाले बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे थे। उनकी सरकार सीमा सुरक्षा से लेकर आतंकवाद और आर्थिक साझीदारी आदि तमाम मसलों पर भारत के साथ सहयोग बनाए रही थी, लेकिन पेंडुलम अब दूसरी दिशा की ओर मुड़ गया है, जैसा कि पहले भी हो चुका है।

बांग्लादेश में मज़हबी कट्टरता का उभार भारत के लिए बड़ा खतरा बन गया है। मुस्लिम बहुल देश बांग्लादेश 1971 में अपनी आज़ादी के बाद से अब तक धर्मनिरपेक्षता की नीति पर चल रहा था, लेकिन अब उग्रवादी इस्लामी तत्वों के बढ़ते असर के साथ यह सब बदल रहा है। जमात-ए-इस्लामी (बांग्लादेश), हिफाजत-ए-इस्लाम, इस्लामी आंदोलन (बांग्लादेश) और बांग्लादेश अवामी ओलामा लीग जैसे मज़हबी संगठनों के नेताओं ने मुल्क को इस्लामी राज में तब्दील करने का खुला आह्वान किया है। बांग्लादेश में युवकों को कट्टरपंथी बनाने और वैश्विक जिहादी नेटवर्कों से उनके जुड़ाव के कारण हमारे सीमावर्ती राज्यों में हिंसा और उग्रवाद को बढ़ावा मिल सकता है।

बांग्लादेश से भारत में खासकर असम, पश्चिम बंगाल और दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध घुसपैठ चिंता की एक स्थायी वजह रही है। बांग्लादेश की आबादी करीब 16 करोड़ है जो इसे दुनिया में सबसे घनी आबादी वाला देश बनाती है। आर्थिक अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, और जलवायु परिवर्तन के कारण कई बांग्लादेशी बेहतर अवसर की तलाश में भारत आते रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के कुछ नेताओं के बयानों से यह आभास होता है कि वह पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार समेत पूरा उत्तर-पूर्व अपना 'लेबेंस्राम' (निवास स्थान) मानते हैं। इस तरह के बयान अच्छे पड़ोसी वाले संबंध के लिए हानिकारक हैं।

बांग्लादेश के कुछ पूर्व सेनाधिकारियों का यह बड़बोलापन आपत्तिजनक है कि वह भारतीय इलाकों पर आसानी से कब्ज़ा कर सकते हैं। ऐसे दावों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि दूसरे देश की सेना अगर हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेगी तब भारत कोई 'लॉलीपॉप नहीं खा रहा होगा।' इस हो-हल्ले में समझदारी की बात बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष जनरल वकार-उज-ज़मां ने की। उन्होंने कहा कि भारत हमारा अहम पड़ोसी है, और बांग्लादेश ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो उसके रणनीतिक हितों के खिलाफ जाता हो।

बहरहाल, भारी संख्या में अवैध घुसपैठ भी भारत के लिए कई चुनौतियां पेश कर रहा है। जैसे, जनसंख्या के स्वरूप में परिवर्तन का खतरा पैदा हो गया है, जिसके बारे में 1990 के दशक में असम के राज्यपाल रहे ले.जनरल एस.के. सिन्हा ने सावधान किया था। असम के कई जिले, खासकर बांग्लादेश से सटे ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणवर्ती जिले मुस्लिम बहुल हो गए हैं। जनसंख्या की दृष्टि से लाखों अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी के कारण खासकर असम में संसाधनों के वितरण और सामाजिक एकता तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर को लेकर तनाव पैदा हो रहा है।

बांग्लादेश खासकर व्यापार, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास और ऊर्जा के मामले में सहयोग के मामले में भारत का एक अहम आर्थिक साझीदार रहा है। पड़ोस में राजनीतिक उथल-पुथल और भारत विरोधी भावनाओं के कारण इन आर्थिक संबंधों में बाधा आ सकती है। सत्ता परिवर्तन के साथ राजनीतिक अस्थिरता के कारण आर्थिक संबंधों में बाधा आई है जिसके चलते सप्लाइ चेन, शुल्क संबंधी नीति, और व्यापार को आसान बनाने वाली सीमा संबंधी व्यवस्था प्रभावित हुई है।

भारत बांग्लादेश में सड़क, रेलवे और बिजली आपूर्ति जैसी कई इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को लागू करने में शामिल रहा है। बांग्लादेश की नई सरकार अगर भारत से कट कर चीन या पाकिस्तान जैसे देशों के साथ करीबी रिश्ता बनाने का फैसला करती है तो इन परियोजनाओं को पूरा करने में देरी होगी या उन्हें रद्द ही करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में भारत के निवेश कुप्रभावित होंगे। इसके अलावा, राजनीतिक अस्थिरता के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़ी इन परियोजनाओं की रफ्तार बनाए रखना मुश्किल होगा।

नई व्यवस्था विदेश नीति को भी बदल सकती है। पाकिस्तानी युद्धपोत बांग्लादेश में स्थित हैं, बांग्लादेश ने अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तानी सैनिकों को बुलाने का अभूतपूर्व फैसला किया है। इससे भारत के रणनीतिक हलकों में खलबली मची है। भारत को अपनी पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर प्रतिकूल पड़ोसियों का पहले से ही सामना करना पड़ रहा है। वह नहीं चाहेगा कि पूर्वी सीमाओं पर भी एक प्रतिकूल पड़ोसी खड़ा हो जाए, क्योंकि इससे उसकी पहले से ही नाजुक सुरक्षा स्थिति पर दबाव बढ़ेगा। सभी संभावित खतरों का प्रभावी मुक़ाबला ही भारत को दक्षिण एशिया में अपनी स्थिति को बांग्लादेश के आंतरिक दबावों से बेअसर रखने में मदद देगा।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े

प्रदेश के सभी स्थान तीर्थ के रूप में होंगे विकसित : मुख्यमंत्री

● श्रीकृष्ण के अनुयायियों के लिए श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र बनेंगे ये तीर्थ ● मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण की जन्म-स्थली के किए दर्शन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व अनवरत जारी है। मध्यप्रदेश में विद्यमान भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े सभी स्थानों को तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण की जन्म-स्थली के परिवार सहित दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा में यह विचार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की समाज हितैषी लीलाओं के साथ उनका शिक्षा ग्रहण करना, मित्रता के उत्कृष्ट भाव का प्रकटीकरण, भगवान परशुराम से सुदर्शन चक्र प्राप्त करने जैसी कई गतिविधियां मध्यप्रदेश की भूमि पर हुई हैं। इन सभी स्थानों को राज्य सरकार तीर्थ के रूप में विकसित करने जा रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देश-दुनिया में बड़ी संख्या में विद्यमान भगवान श्रीकृष्ण के अनुयायियों के लिए मध्यप्रदेश में विकसित यह तीर्थ श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र बनेंगे। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष पूरे प्रदेश में गौवर्धन पूजा और गीता जयंती का धूमधाम से आयोजन किया गया। प्रदेश में जन्माष्टमी भी पूर्ण उल्लास और आनंद के साथ मनाई जाएगी।

प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को मिलेगा प्रोत्साहन

● मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वृंदावन में बांके बिहारी लाल के किए दर्शन- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वृंदावन के कण-कण में कृष्ण और रज-रज में राधे रानी का वास है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को अपने मथुरा प्रवास के दौरान कन्हैया की लीला स्थली वृंदावन में स्वस्तिवाचन के साथ सांवरे सलोने ठाकुर जी और ठकुरानी श्री राधिका रानी के युगल विग्रह रूप 'श्री बांके बिहारी लाल' के दर्शन भी किए।

● कुल्हड़ वाली लस्सी का लिया आनंद- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वृंदावन में दर्शन के बाद सपरिवार कुल्हड़ वाली लस्सी का आनंद लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हजारों की संख्या में मौजूद भगवान श्रीकृष्ण के भक्तों के बीच वृंदावन के भक्तिमय वातावरण ने लस्सी का आनंद दोगुना कर दिया। दुकानदार द्वारा लस्सी का पेमेंट यूपीआई से लेने पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह नए और बदलते भारत का प्रतीक है।

हिंदू धार्मिक स्थलों पर मस्जिदों का निर्माण 'घाव' इसकी 'सर्जरी' जरूरी

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर अदालत के आदेश का जोरदार बचाव किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अदालत ने सर्वे का आदेश इसलिए दिया था कि जिससे यह पता लग सके कि संभल की शाही जामा मस्जिद हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। उन्होंने हिंदू धार्मिक स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को एक 'घाव' बताया और कहा कि इसकी 'सर्जरी' किए जाने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो यह कैंसर बन सकता है।

वक्फ बोर्ड को बताया माफिया का बोर्ड- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड की भी आलोचना की और इसे माफिया का बोर्ड बताया और संकल्प लिया कि अवैध रूप से कब्जा की गई एक-एक इंच जमीन को वापस लिया जाएगा और इस पर जनकल्याण की परियोजनाओं का काम किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को हिंदू और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया। योगी ने अपने राजनीतिक विरोधियों से कहा कि वे भारत की आध्यात्मिक विरासत को स्वीकार करें।

सुप्रभात

वर्षा की प्रतीक्षा की जाती है
और वसन्त के आगमन की तैयारी
ज्यों जीवन भर करते हैं लोग सुख की प्रतीक्षा
करता है कोई सुखों के बीच
मृत्यु की तैयारी
उन लोगों में से नहीं हूँ
जो सुनते हैं राग वसन्त बहार केवल
वसन्त के दिनों में
प्रेम के दिनों में लिखते हैं प्रेम की कविता
आसन्न मृत्यु की घड़ी में कहते
हैं संसार को माया
चौंकाती नहीं मृत्यु मुझे
रुलाती है इतने सुदूर एकाकीपन में जहाँ
मुझे भी मनाही हो प्रवेश की
जीवन चौंकाता है क़दम-क़दम पर
धारासार बरसती साँसों के बीच सूख कर
रुलाता है जीवन जितना
दोगुना हँसाता है
कैसा लगे जो कभी हवाई झूले में
अकेले बैठना पड़ जाए ?
भय और रोमांच की मिलीजुली
कँटीली-सी गुदगुदी
तलुवों पर पता चलती है सबसे पहले
इसलिए भी चलती हूँ धीमे
कि मेरे पाँव के तलुवों में सिहरनों
का रेतीला टीला है
नदी के नीचे बहती है एक कथा
पेड़ की छाँव में रहती है कविता
प्रेमी की छाती में गड़ा होता प्रेयसी के
तिलों का रहस्य
वसन्त, प्रेम और मृत्यु यूँ रहते हैं मेरे साथ
ज्यों जुगनू की देह के अँधेरे हिस्सों में
रहता है पीला प्रकाश।

- बाबुषा

हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान ने किया सुसाइड

डल्लेवाल जहां 45 दिन से आमरण अनशन कर रहे

चंडीगढ़ (एजेंसी)। हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के दौरान गुरुवार को एक किसान ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। किसानों के बताया- गुरुवार सुबह लंगर स्थल के पास ही तरनतारन जिले के पहूविंड गांव में रहने वाले रेशम सिंह (55) ने सल्फास खाया। उसे पटियाला के राजिंदरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। किसान नेता तेजबीर सिंह ने कहा कि रेशम शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 11 महीने से आंदोलन के बावजूद सरकार की तरफ से इसका समाधान न निकालने से नाराज था। इससे पहले भी 14 दिसंबर को किसान रणजोध सिंह ने भी सल्फास खा लिया था।

म.प्र. में देश के पहले हाइड्रोजन-सीएनजी वाहन का अनावरण

● गडकरी बोले- इथेनॉल, सीएनजी, ईवी को दे रहे बढ़ावा 2 किलोलीटर में 40 किमी चलेगा ये वाहन

पीथमपुर/इंदौर (नप्र)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने देश के पहले हाइड्रोजन-सीएनजी बाजा व्हीकल का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि हम लगातार इथेनॉल, बायोडीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ये वाहन 2 किलोलीटर में 40 किमी तक चलेगा।

गडकरी ने गुरुवार को नेट्रैक्स द्वारा आयोजित बाजा इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें देशभर से 100 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्र भाग लेने पहुंचे हैं। इसमें ऑफ रोड एटीवी (ऑल-टेरेन व्हीकल) का निर्माण कर परीक्षण से गुजारा जाता है। ये आयोजन पिछले 17 साल से किया जा रहा है।

● गडकरी ने कहा-किसान बनेगा ईंधनदाता- गडकरी ने कहा कि वाले दिनों में हमारे देश का किसान हमारा ईंधन दाता बनेगा। मेरे पास इनोवा कार है, जो इथेनॉल और बिजली से चल रही है। यह जीरो प्रतिशत प्रदूषण करती है। भारत की सभी बड़ी कंपनियां भविष्य को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल-डीजल के अलावा अन्य ईंधन विकल्पों पर लगातार काम कर रही हैं।

● सीएनजी बाइक भी बाजार में उपलब्ध- गडकरी ने कहा कि सीएनजी से चलने वाली बाइक बाजार में उपलब्ध हैं, जो एक रुपए प्रति किलोमीटर में चल रही है। हम वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अभी ट्रैक्टर भी बाजार में उतारा है, जो सीएनजी से चल रहा है।

● ऑटो इंडस्ट्री में साढ़े 4 करोड़ नौकरियां उपलब्ध- नितिन गडकरी ने कहा कि पिछले 5 साल में चार करोड़ 50 लाख नौकरियां ऑटो इंडस्ट्री में मिल रही हैं।

अपात्र होने पर 1.63 लाख लाड़ली बहनों को इस बार नहीं मिलेगा पैसा

60 साल से अधिक उम्र होने पर सरकार ने काटे नाम, 1.26 करोड़ महिलाओं को जारी होगी 20वीं किस्त

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 1 लाख 63 हजार महिलाओं को इस बार 1250 रुपए की किस्त नहीं मिलेगी। इन महिलाओं की उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है। ऐसे में महिला और बाल विकास विभाग ने इन्हें अपात्र घोषित कर दिया है।

अब जनवरी 2025 में 1.26 करोड़ महिलाओं को ही 1250 रुपए की किस्त मिल सकेगी। इससे पहले 11 दिसंबर 2024 को 1.28 करोड़ महिलाओं के खाते में 1572 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे।

जनवरी 2025 में 20वीं किस्त मिलने वाली है। इसके लिए विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। अनुमान है कि सरकार 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन आयोजित दो अलग-अलग कार्यक्रमों के दौरान राशि ट्रांसफर कर सकती है।

सरकार ने किस्त देने के लिए 31 दिसंबर 2024 को 5 हजार करोड़ का कर्ज भी ले लिया है, जिसका भुगतान सरकार को एक जनवरी 2025 को हो गया है।

नए नाम नहीं जुड़ रहे, पुराने घटते जा रहे

इस योजना में नए नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं, इसके उलट 20 माह से लागू इस योजना में पात्र महिलाओं के नाम उम्र और अन्य शर्तों के आधार पर कटते जा रहे हैं। इसी कारण इनकी संख्या 2023 और 2024 में बढ़ने की बजाय घटी है। जब योजना शुरू हुई थी तो कुल 1 करोड़ 31 लाख 35 हजार 985 आवेदन आए थे। इसके बाद 2 लाख 18 हजार 858 नाम आपत्तियों को आधार बनाकर काटे गए थे। जिसके बाद यह संख्या 1 करोड़ 29 लाख 5 हजार 457 रह गई थी। अब यह संख्या एक करोड़ 26 लाख से अधिक तक पहुंचने वाली है।

ऐसे घट रहे पात्र महिलाओं के नाम

योजना में पात्र महिलाओं के नाम कम होने को लेकर जो जानकारी अफसरों ने दी है, उसके अनुसार इसकी सबसे बड़ी शर्त महिला की उम्र साठ साल पूरी होना है। इसके अलावा योजना का लाभ पाने वाली जिन महिलाओं की मृत्यु हो जाती है उनके नाम भी हर माह डिलीट किए जाते हैं। साथ ही जो महिला पात्रता की शर्तों के आधार पर लाभ का परित्याग करने के लिए विभाग को लिखित में जानकारी देती हैं, उनके भी नाम काटे जाते हैं।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 18 °c

न्यूनतम 13°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शुक्रवार, 10 जनवरी 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

विश्व हिंदी दिवस - विशेष

दुनिया की तीसरी प्रचलित भाषा होने पर भी हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है?

सुदर्शन व्यास

(लेखक शोधार्थी एवं पत्रकार हैं)

इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदी अब धीरे - धीरे रोजगार की भाषा बनती जा रही है। हिंदी राष्ट्रीय स्तर हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर, हर स्तर पर छाई हुई है। अस्सी - नब्बे के दशक के बाद जब तकनीकी क्रांति जोर पकड़ने लगी तो अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ।

तकनीकी वस्तुओं का प्रचलन अधिक हुआ, कंप्यूटर-मोबाइल जैसे तकनीक उपकरणों आदि का वर्चस्व स्थापित हो गया। इन सब कार्यों में अंग्रेजी का भरपूर उपयोग होता था, तब ऐसा लगा कि अंग्रेजी छा जाएगी और हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि हिंदी और आगे बढ़ती गई। हिंदी की लोकप्रियता हर मापदण्डों को पछाड़ते हुई और भी ज्यादा बढ़ी है।

इन सब बातों के अलावा एक कसक भी है कि हिंदी बदलते दौर के साथ अपना स्वरूप भी बदल रही है। कई ऐसे तीखे सवाल भी है, जो हिंदी हमसे पूछती है लेकिन उनके जवाब हमारे पास नहीं होते। कसक ये है कि हम हिंदी भाषी होने पर गर्व से फूले नहीं समाते लेकिन हिंदी के उच्चारण, वर्तनी और लेखन में शुद्धता पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं।

एक उदाहरण ही लें तो बाज़ार में लोग हिंदी भाषा में अपनी दुकानों के नामों का उपयोग करते हैं लेकिन ज्यादातर लोग इस बात पर कभी गौर नहीं करते कि हिंदी में अशुद्धियां कितनी ज्यादा है ? इसका कारण है कि हमने अब हिंदी लिखने के लिए गूगल का सहारा लेना शुरु कर दिया है, अब पत्र और डायरी लिखना बीते ज़माने की बातें हो गई।

बाकि, हिंदी दिवस पर हमारा चिंतन इसी बात को लेकर रहता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है। हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में हिंदी चिंतकों और प्रेमियों द्वारा उपयोग किये गए शेर, शायरी से लेकर लच्छेदार भाषणों का केंद्र यही होता है, लेकिन असलीयत यही है कि हिंदी ग्लोबल तो हो रही है लेकिन कहीं न कहीं सिकुड़ती भी जा रही है।

हालांकि, हिंदी का मान बढ़ाने में महती भूमिका मीडिया जगत के अलावा हिंदी फिल्मों, टेलीवीजन पर बनने वाले नाटकों ने भी निभाई है। यदि हम बात क्लिष्ट अर्थात् शुद्ध हिंदी की करें तो व्यक्ति व्याकरण के भंवर में उलझ सकता है। यकीनन, शुद्ध हिंदी सबके बस की बात नहीं है, तभी तो सामान्य बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी समेत तमाम भाषाओं के शब्दों का उपयोग हम हिंदी में सामान्य रूप से करते हैं। हिंदी ने हर भाषा को स्वीकार कर उसके शब्दों को अपने अस्तित्व में ढाल लिया, इसीलिए इसे भाषाओं की मां का दर्जा दिया गया है, क्योंकि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें भावनाएं भी सहज रूप से प्रतीत होती है।

यदि हम बात रोज़गार की करें तो इसे रोज़गार परक बनाने में मीडिया की बड़ी भूमिका है, इस जगत में अनेक हिंदी समाचार चैनलों, समाचार पत्र व पत्रिकाओं के आगमन से पत्रकारिता के क्षेत्र में रोजगार की बिल्कुल भी कमी नहीं है। अब तो गूगल ने भी हिंदी का महत्व समझते हुए हिंदी पर काफी काम किया है, इतना ही नहीं माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर के निर्माण के समय हिंदी को पूरा महत्व देता है और हिंदी फॉन्ट की उपलब्धता आज बेहद आसान हो गई है। इन सबका एक ही प्रमुख कारण है कि हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बनकर अपना अस्तित्व समूचे विश्व के सामने बना रही है। इस भाषा के बोलने वालों की संख्या अब 50 करोड़ को पार कर गई है तथा इस भाषा को समझने वाले लोगों की संख्या पूरे विश्व में 1 अरब से भी ज्यादा है। अत: हिंदी में निरंतर रोजगार की संभावनाएं बढ़ती ही जा रही है। अब वो समय गया जब लोग कहते थे कि अंग्रेजी रोजगार की भाषा है।खैर, चिंतन फ़िर भी जारी है कि हिंदी भले ही समूचे विश्व की तीसरे नंबर की भाषा बन गई हो। आज दुनिया भर में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में हिंदी तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के 22वें संस्करण इथोनोलॉज में बताया गया कि दुनियाभर की 20 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में 6 भारतीय भाषाएं हैं, जिनमें हिंदी तीसरे स्थान पर है, यानि दुनियाभर में 61.5 करोड़ लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन भारत में हिंदी आज भी राष्ट्रभाषा के दर्जे से अछूती है।

संक्षिप्त समाचार

आसाराम के जेल से बाहर आने की राह आसान नहीं

- पहले भी हाईकोर्ट में पांच बार खारिज हो चुकी अर्जी

जोधपुर (एजेंसी)। आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से गुजरात के गांधीनगर रेप केस में 7 जनवरी को अंतरिम जमानत मिल गई। इसके बाद 8 जनवरी को राजस्थान हाईकोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई। अब चर्चाएं हैं कि आसाराम शीर्ष अदालत से मिली राहत को आधार बनाएगा। इसी तर्क के साथ उसे जोधपुर में नाबालिग से रेप के मामले में भी बेल मिल सकती है। आसाराम जोधपुर में अपने ही आश्रम की नाबालिग के साथ यौन दुराचार का दोषी है और आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। लीगल एक्सपर्ट की

मानें तो आसाराम को पॉक्सो के मुकदमे में बेल मिलने की दूर तक कोई संभावना ही नहीं है। आसाराम कोर्ट में केवल एसएएस (सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस) लगा सकता है, जो सजा निलंबन या स्थगन की याचिका होती है। चूंकि राजस्थान हाईकोर्ट इससे पहले 5 बार आसाराम की एसओएस खारिज कर चुका है। अभी पांचवीं याचिका पर ही सुनवाई पेंडिंग है। ऐसे में बुधवार को छठी बार लगाई गई याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा, इसकी संभावनाएं कम ही हैं। इतना ही नहीं लोअर कोर्ट, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 12 बार उसकी अर्जी खारिज हो चुकी है।

इसरो ने स्पेडेक्स मिशन की डॉकिंग दूसरी बार टाली

- दो स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोडना था

बेंगलुरु (एजेंसी)। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 9 जनवरी को होने वाले स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को बुधवार को फिर टाल दिया। इसरो ने 2 स्पेस सैटेलाइट के बीच ज्यादा अंतर का पता लगने के बाद इसे टाल दिया है। अगली तारीख का ऐलान नहीं किया है। इसरो ने कहा- सैटेलाइट के बीच की

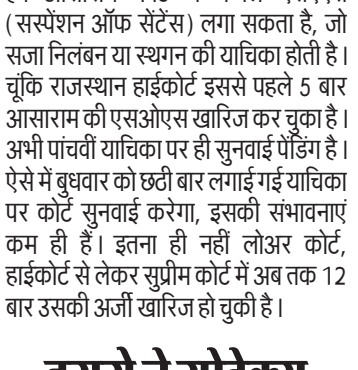

दूरी को 225 मीटर तक कम करने के लिए किए गए ऑपरेशन के दौरान यह समस्या आई। लिहाजा 9 जनवरी को होने वाली डॉकिंग (जोड़ा जाना) प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। सैटेलाइट सुरक्षित हैं। इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत पीएसएलवी-ए 60 रॉकेट से दो स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किमी ऊपर डिप्लॉय किए गए थे। स्पेसक्राफ्ट्स को कनेक्ट करने की प्रक्रिया जारी है।

अप्रवासी जहां भी जाते हैं उसे अपना बना लेते हैं

- पीएम बोले-अप्रवासियों के दिल में हमेशा से धड़कता है भारत
- ओडिशा में बोले-इससे दुनिया में मेरा सिर ऊंचा रहता है
- आप भविष्य में मेड इन इंडिया प्लेन से भारत आएंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। मोदी ने कहा- अप्रवासी जहां जाते हैं उसे अपना बना लेते हैं। इसके बावजूद उनके दिल में हमेशा भारत धड़कता है। इसी के चलते दुनिया में मेरा सिर ऊंचा रहता है। पीएम ने आगे कहा कि, भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है। वो दिन दूर नहीं जब आप (अप्रवासी भारतीय) किसी मेड इन इंडिया प्लेन से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने आएंगे।

इस कार्यक्रम को त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ने भी वर्चुअली संबोधित किया। मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को भी हरी झंडी भी दिखाई। यह भारतीय प्रवासियों के लिए स्पेशल ट्रेन है, जो दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चली और तीन सप्ताह तक कई ट्रेरिस्ट

प्लेसेज तक जाएगी। विदेश मंत्रालय की प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत इसका संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम के लिए 70 देशों से 3 हजार से ज्यादा प्रतिनिधि ओडिशा पहुंचे हैं। यह सम्मेलन 10 जनवरी तक चलेगा।

- **मैंने हमेशा भारतीय डाइसपोरा को भारत का राष्ट्रदूत माना है-** मुझे खुशी होती है जब दुनिया में आप सभी साथियों से बात करता हूं। जो प्यार मिलता है उसे भूल नहीं सकता। आपका स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। मैं सभी का निजी तौर पर आभार करता हूं। आपको थैंक यू भी बोलना चाहता हूं। वो इसलिए क्योंकि आपकी वजह से मुझे दुनिया में गर्व से सिर ऊंचा रखने का मौका मिलता है। बीते दस साल में मेरी दुनिया के अनेक लीडर से मुलाकात हुई है। अपने देश के भारतीय डाइसपोरा की बहुत प्रशंसा करता है। इसका एक बड़ा कारण वो सोशल वैल्यूज हैं जो आप सभी वहां की सोसाइटी में दिखाते हैं। हम सिर्फ मदर ऑफ डेमोक्रेसी ही नहीं है बल्कि जीवन का हिस्सा है। हमें विविधता सिखानी नहीं पड़ती हमारा जीवन ही इससे चलता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव करेंगे वानिकी सम्मेलन एवं आईएफएस मीट का शुभारंभ

भोपाल(नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में पं. खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय सभागृह नेहरू नगर भोपाल में 10 जनवरी को प्रात: 11 बजे वानिकी सम्मेलन एवं आईएफएस मीट का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार करेंगे। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव वन श्री अशोक वर्णवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री असीम श्रीवास्तव और आईएफएस अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रवासी भारतीय दिवस पर दी बधाई

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रवासी भारतीय दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि देश, जीवन शैली और परिस्थितियों में विभिन्नता के बावजूद भारतीय संस्कृति और मानवता के धागे से सभी भारतीय हमेशा समरस रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी से भारत के नव-निर्माण में संकल्पित होकर सहभागी होने का आह्वान किया है।

वर्तमान टीएसटी चुने हुये अमीरों की, अमीरों के द्वारा अमीरों के लिये: टी.एस. सिंहदेव

भोपाल (नप्र)। छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने आज मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि वर्तमान जी.एस.टी. चुने हुये अमीरों की, अमीरों के द्वारा, अमीरों के लिये आम आदमी के जेब से पैसे निकाल रही है। श्री सिंह ने कहा कि जी.एस.टी. वर्तमान में जिन प्रावधानों से लागू है उसमें अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और मिडिल क्लास एवं निम्न आय वर्ग और अधिक जी.एस.टी. चुका रहा है। उन्होंने कहा कि देश के 10 प्रतिशत अमीर 3 से 4 प्रतिशत जी.एस.टी. कर दे रहे हैं जबकि देश की निचली 50 प्रतिशत आय वर्ग की आबादी 64 प्रतिशत जी.एस.टी. का भार वहन कर रही है जिससे उसके हाथ में जो पैसा वो अपने घर के लिये, परिवार के लिये वहन कर सकती है, वह जी.एस.टी. के रूप में उनसे सरकार ले लेती है। श्री सिंह ने कहा कि कर पटाने में व्यवसाईयों को अत्यधिक दिक्कतें हो रही हैं और वर्तमान में 9 जी.एस.टी. के दर प्रचलन में हैं। इनका सरलीकरण अत्यावश्यक है और अधिकतम 2 या 3 जी.एस.टी. के स्लैब दर होना चाहिये। उन्होंने कहा कि सरकारें आय के स्त्रोत बनाने के लिये वस्तुओं पर जी.एस.टी. बढ़ा रही है, उदाहरण के लिये हाल ही में पोपकॉर्न के 3 अव्यवहारिक दर 5, 12 एवं 18 कर दिये हैं। श्री सिंह ने कहा कि जहाँ मध्यम और निम्न आय वर्ग से अधिक जी.एस.टी. ली जा रही है, वहीं देश के कॉपरेट घरानों को कॉपरेट टैक्स में 2 लाख करोड़ की वार्षिक छूट दी जा रही हैं, निम्न आय वर्ग से जी.एस.टी. लेना पूर्णत: अव्यवहारिक है वहीं कॉपोरेट टैक्स में छूट क्यों दी गई आप स्वयं समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य वस्तुओं पर जी.एस.टी. समाप्त होना चाहिये वहीं पैन्सिल जैसी वस्तुओं पर जी.एस.टी. लगाना औचित्यहीन है और स्वास्थ सुरक्षा के लिये जो नागरिक इन्श्योरेन्स कराते हैं उन्हें 18 प्रतिशत जी.एस.टी. देनी पड़ रही है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार को जहाँ जी.एस.टी. की दरों का सरलीकरण करना चाहिये, वहीं जी.एस.टी. के दरों के बढ़ाने के बजाए कर चोरी रोक कर उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये जी.एस.टी. से राजस्व बढ़ा कर जी.एस.टी. की दरें भी कम की जा सकती हैं साथ ही आमदनी में भी इजाफा किया जा सकता है।

राहुल गांधी आइसक्रीम शॉप पर गए, कोल्ड कॉफी बनाई

बोले-छोटे काम वालों को आसानी से लोन नहीं मिलता, यूपी में मिले मोची का जिक्र भी किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। राहुल गांधी दिल्ली में एक आइसक्रीम शॉप पर गए, जहां उन्होंने कोल्ड कॉफी बनाई। केवेंटर्स ब्रांड की इस शॉप में जाने और उसके ओनर्स से चर्चा का एक वीडियो राहुल ने एक्स पर शेयर किया है। राहुल ने लिखा कि आप नई पीढ़ी और नए बाजार के लिए विरासत ब्रांड को कैसे बदल सकते हैं। ये केवेंटर्स के युवा संस्थापकों ने मुझे बताया। केवेंटर्स जैसे निष्पक्ष व्यवसायों ने पीढ़ियों से हमारी आर्थिक वृद्धि को गति दी है।

इसलिए हमें उनका समर्थन करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बीच केवेंटर्स के ओनर्स अमन और अगस्त्य ने उनसे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया- मैं केवेंटर्स को देख रहा हूं और निवेश का फैसला करने की कोशिश कर रहा हूं। चर्चा के दौरान यूपी के सुल्तानपुर में मिले मोची रामचैत के बारे में भी बात की। राहुल ने कहा कि हमारे देश में बैंक बड़े बिजनेसमैन को तो आसानी से लोन दे देते हैं, लेकिन छोटे काम करने वालों को पैसा नहीं

मिलता। राहुल गांधी जब ओनर्स से बातचीत कर रहे थे, तब शॉप के बाहर खड़ी एक बुजुर्ग महिला को उन्होंने अंदर बुलाया। उनसे हाल-चाल पूछा। इस बीच उस महिला ने राहुल को अपने घर बुलाया और कहा कि उसका घर शॉप के ऊपर है। राहुल जब उसके घर पहुंचे तो दरवाजे की चाबियां गुम हो गई। बातचीत के दौरान महिला ने बताया कि वह राजीव गांधी से तब मिलने गई थी, जब वे रेसकोर्स वाले घर में रहा करते थे। दरवाजा न खुलने पर राहुल ने महिला से कहा कि वे अगली बार उसके घर जरूर आएंगे।

भाजपा घोषणा पत्र समिति के शिवनारायण बने सिया के अध्यक्ष

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के पूर्व आईएएस और भाजपा घोषणा पत्र समिति के प्रमुख शिवनारायण सिंह चौहान चेयरमैन बनाए गए है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार डाक्टर सुनंदा सिंह रघुवंशी प्राधिकरण में सदस्या बनायी गयी है। चेयरमैन और सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। इसके साथ ही अधिसूचना में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का भी गठन किया है। समिति में राकेश श्रीवास्तव अध्यक्ष बनाए है वहीं विजय कुमार अहिरवार, डा राकेश कुमार पांडेय, डा पल्लवी भटनागर, डा सुनिता सिंह और डा सुशील मंडेरिया सदस्य बनाए गए है। मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे।

भाजपा के अध्यक्षों की घोषणा होगी जिलों में

भोपाल। बहुप्रतीक्षित भाजपा के जिला अध्यक्षों की घोषणा का प्लान बदल दिया है। जिला अध्यक्षों की घोषणा आज हो सकती है। अब जिलाध्यक्षों की घोषणा जिलों में ही होगी । घोषणा से पहले जिला कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसमें जिला अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा।

राजीव सिंह ने कांग्रेस संगठन प्रभारी पद छोड़ा, पहली बार संगठन में दो प्रभारी बनाए, प्रियव्रत और कामले को मिली कमान

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस ने अपने नेताओं को अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें अलग-अलग डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया गया है। संगठन प्रभारी से इस्तीफे की पेशकश करने वाले राजीव सिंह को जीतू पटवारी ने अपने पॉलिटिकल एडवाइजर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं संजय कामले संगठन प्रभारी बनाए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस ने गुरुवार को इलेक्शन मैनेजमेंट से लेकर पॉलिटिकल एडवाइजर, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, यूथ कांग्रेस, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, महिला कांग्रेस और एनएसयूआई तक कुल 35 विभागों के इंचार्ज नियुक्त किए गए हैं। राघौगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह को यूथ कांग्रेस का इंचार्ज बनाया गया है। वहीं हिना कांवरे को महिला कांग्रेस का इंचार्ज बनाया गया है। प्रियव्रत सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ ही इलेक्शन मैनेजमेंट का इंचार्ज बनाया गया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सरकारी कर्मचारी संगठनों से कॉर्डिनेशन की जिम्मेदारी निभाएंगे। केके मिश्रा को पीसीसी चीफ का मीडिया एडवाइजर बनाया गया है। जेपी धनोपिया इलेक्शन कमीशन और लीगल वर्क, आनंद राय सिविल सोसायटी आउटरीच देखेंगे।

आजम खान के चेलों को महिला सम्मान सिखाऊंगी

बीजेपी नेता जयाप्रदा बोलीं-यूपी के मुरादाबाद कोर्ट में हाजिर हुईं

मुरादाबाद (एजेंसी)। रामपुर की पूर्व सांसद और एक्ट्रेस जयाप्रदा गुरुवार को मुरादाबाद कोर्ट में पेश हुईं। इसके बाद उन्होंने कहा- वक्त जरूर बदला है, लेकिन

महिलाओं के लिए इंसाफ पाना अभी भी इतना आसान नहीं है। इसके लिए संघर्ष और इंतजार दोनों करने पड़ते हैं। सीता मैया को भी 14 साल का इंतजार करना पड़ा था। जमाना बदल गया है, लेकिन महिलाओं के लिए सम्मान की लड़ाई लड़नी हो तो संघर्ष और इंतजार तो करना ही पड़ता है लेकिन, मैं हार मानने वाली नहीं हूं। मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले आजम के 6 चेलों, उनके बेटे व सांसद एसटी हसन को सिखाकर रहूंगी।

तेजस विमानों की स्लो डिलीवरी पर एयरफोर्स चीफ ने जताई चिंता

- बोले-40 जेट्स फोर्स को अभी तक नहीं मिले, चीन जैसे देश ताकत बढ़ा रहे

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडियन एयरफोर्स के चीफ एपी सिंह ने बुधवार को तेजस लड़ाकू विमानों की डिलीवरी पर हो रही देरी को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि 2009-2010 में ऑर्डर किए गए 40 तेजस विमानों की पहली खेप अभी तक नहीं मिली है। सिंह ने बताया कि तेजस फाइटर जेट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1984 में हुई थी। पहला विमान 2001 में उड़ा, लेकिन 15 साल बाद इसे 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया।

वायुसेना के लिए ऑर्डर किए गए पहले 40 तेजस विमानों की डिलीवरी अब तक पूरी नहीं हो सकी है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ये बातें 21वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार के दौरान कहीं। चीन का 6 एमएम जनरेशन जेट की टेस्टिंग की चीन ने हाल ही में अपने 6 एमएम जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का ट्रायल किया है।

इस पर एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हमारे उत्तरी और पश्चिमी पड़ोसी तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं। चीन की नई तकनीक और संख्या दोनों ही चिंता का विषय हैं। दरअसल, चीन ने अमेरिका के बाद दो स्टेल्थ फाइटर जेट विकसित किए हैं। अब उनका 6 एमएम जनरेशन फाइटर जेट भी ट्रायल के लिए तैयार है।

30 फीट दूर था टाइगर शिकार होने से बचे लोग

जंगल की सैर करने निकले थे भोपाल के साइकिलिस्ट; तभी सामने आ गया बाघ

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कुछ साइकिलिस्ट जंगल की सैर करने निकले। तभी उनके सामने टाइगर आ गया। 2 से 3 मिनट तक टाइगर घूमता रहा और फिर झाड़ियों में चला गया। बाघ के अचानक सामने आने से लोग सहम गए। जब टाइगर आगे बढ़ा, तब वे जा सके। बाघ के मूवमेंट का वीडियो गुरुवार को सामने आया है। वीडियो चार दिन पुराना बताया जा रहा है। वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि यह अवधपुरी के दिलीप सिंह ने बनाया है, जो साइकिलिस्ट भी हैं। वे जब साथियों के साथ जंगल से गुजर रहे थे, तभी टाइगर उनके सामने आया। साइकिलिस्ट दिलीप सिंह ने बताया कि...जंगल से गुजर रहे थे, तभी झाड़ियों से टाइगर निकल आया।

वो हमसे सिर्फ 30 फीट दूर था। जैसे ही उसे देखा सहम गए। 2-3 मिनट तक टाइगर आसपास मंडराता रहा। हम भी बिना हिले-डुले खड़े रहे। यदि थोड़ा सा भी बॉडी मूवमेंट होता तो टाइगर हमला कर देता। शुक्र है...सभी सुरक्षित बच गए और वापस लौट आए।

साइकिल से आउटिंग पर गए थे

अवधपुरी निवासी दिलीप सिंह ने बताया, वीडियो भोजपुर मंदिर के पीछे चिकलोद जंगल का है, जो उन्होंने ही बनाया था। चार दिन पहले रविवार को 25-30 साथी साइकिल से आउटिंग पर गए थे। भोपाल से सब साथ में निकले। चिकलोद जंगल से गुजर रहे थे, तभी अचानक सामने बाघ आ गया। अचानक बाघ के दीदार होने की खुशी के साथ खौफ भी था। टाइगर और हमारे बीच की दूरी कुछ फीट की ही थी।

चिकलोद रेंज में कई टाइगर

भोपाल से जुड़े रायसेन के चिकलोद रेंज में कई टाइगर है। इनके मूवमेंट के मामले सामने आते रहे हैं। करीब चार महीने पहले चिकलोद रोड वरूखार के पास बाघिन का मूवमेंट देखने को मिला था। कई बार वन विभाग को टाइगर का रेस्क्यू तक करना पड़ा था।

चिकलोद रेंज में शिकार भी हो चुका- भोपाल से 35 किलोमीटर दूर चिकलोद रेंज के आशापुरी गांव के जंगल में शिकारियों ने 14 जुलाई 2024 को गोली मारकर बाघ का शिकार किया था। शिकारी बाघ की स्किन, चार-चार नाखून और दांत ले गए थे। वहीं, पंजा शरीर से दूर पड़ा मिला था।

सेंट्रल जेल में मिले ड्रोन को डॉक्टर ने अपना बताया

- **पुलिस कमिश्नर के निरीक्षण के दौरान रिमोट लेकर जेल पहुंचे, आरजीपीवी में भी मिला संदिग्ध ड्रोन**

भोपाल (नप्र)। पुलिस कमिश्नर हरीनारायण चारी मिश्रा ने गुरुवार दोपहर भोपाल सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने वॉच टावर पर बल और जेल परिसर में कैमरों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान ही बुधवार को जेल में मिले संदिग्ध ड्रोन को एक डॉक्टर ने स्वयं का बताया। वह ड्रोन का रिमोट लेकर जेल परिसर में पहुंचे थे। इस रिमोट ड्रोन को ऑपरेट कर पुलिस ने चेक भी किया। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने ड्रोन की फोरेंसिक जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

जेल अधीक्षक राकेश भांगरे के मुताबिक डॉक्टर स्विग्नल जैन महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में प्रोफेसर हैं। वह द्वारका धाम में रहते हैं। गुरुवार की सुबह उन्होंने स्वयं कॉल कर मुझे बताया कि जेल परिसर में मिला ड्रोन उन्हीं का है। न्यूज पेपर में खबर के साथ लगे फोटो से उन्होंने ड्रोन की पहचान की है। दोपहर

के समय वह ड्रोन का रिमोट लेकर जेल आए। इस रिमोट से ड्रोन ऑपरेट भी हो रहा था। उन्होंने लिखित पत्र भी सौंपा है, जिसमें ड्रोन स्वयं का होने का दावा किया गया है।

दिल्ली से खरीदा गया था ड्रोन

डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि ड्रोन को उन्होंने बेटे के लिए दिल्ली से खरीदा था। 31 दिसंबर 2024 को वह ड्रोन लेकर आईटी पार्क पहुंचे। यहां बेटे के साथ उन्होंने ड्रोन उड़ाया। ऊंचाई पर जाने के बाद ड्रोन से संपर्क टूट गया। इसके बाद वह लापता हो गया। आस पास काफी तलाशने पर भी ड्रोन नहीं मिला। अखबारों में खबर और ड्रोन का फोटो देखा। ड्रोन खरीदी से जुड़े दस्तावेज भी उन्होंने पुलिस को सौंपे हैं। हालांकि पुलिस मामले की सभी एंगल पर जांच कर रही है।

आरजीपीवी में भी मिला ड्रोन

गांधी नगर में ही स्थित आरजीपीवी कैंपस में भी एक संदिग्ध ड्रोन मिला है। हालांकि जेल में मिले ड्रोन और यूनिवर्सिटी में मिले ड्रोन के कलर से लेकर मैन्यूफैक्चरिंग तक सब अलग-अलग है। पुलिस ने इस ड्रोन को भी जब्त कर जांच शुरू कर दी है।

एचएमपीवी को लेकर एम्स का सुरक्षा अलर्ट

भीड़ वाली जगहों पर मास्क जरूरी, ठंडे मौसम में सक्रिय होता वायरस

भोपाल (नप्र)। मलेशिया और चीन के बाद भारत में एचएमपीवी वायरस के तीन मामले सामने आए हैं, जिससे सोमवार को यह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहा। एम्स भोपाल ने एचएमपीवी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुरक्षा और जागरूकता के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

एम्स ने वायरस के फैलाव को रोकने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। एचएमपीवी एक श्वसन वायरस है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों और सांस लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यह छोटे बच्चों, बुजुर्गों और जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, उनके लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। साथ ही, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्वास्थ्य विभाग को वायरस की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

कैसे फैलता है एचएमपीवी वायरस- एम्स भोपाल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. देवाशीष विश्वास ने बताया कि यह वायरस मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली श्वसन बूंदों से फैलता है। इसके अलावा, संक्रमित व्यक्ति से

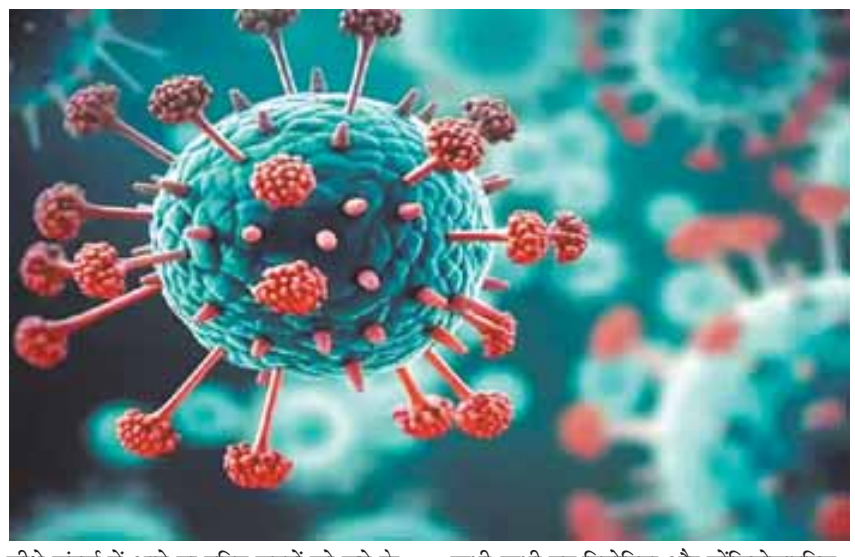

सीधे संपर्क में आने या दूषित सतहों को छूने के बाद आंख, नाक या मुंह को छूने से भी संक्रमण हो सकता है।

एचएमपीवी के सामान्य लक्षणों में बुखार, नाक बहना, गले में खराश, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, घरघराहट और थकान शामिल हैं। कभी-कभी यह निमोनिया और ब्रोंकियोलाइटिस भी पैदा कर सकता है। सामान्य रूप से स्वस्थ लोग बिना किसी समस्या के ठीक हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा, हृदय रोग जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए यह वायरस ज्यादा खतरनाक हो सकता है।

एम्स में एचएमपीवी की जांच

एचएमपीवी वायरस की जांच आरटीपीसीआर तकनीक से की जाती है, जो एम्स भोपाल में उपलब्ध है। एम्स भोपाल श्वसन संक्रमणों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। यहां अनुभवी स्वास्थ्यकर्मियों की टीम और उन्नत प्रयोगशालाएं हैं, जो आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करती हैं। एम्स भोपाल में श्वसन वायरस की जांच के लिए आरटी-पीसीआर तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो एचएमपीवी का पता लगाने का सबसे सही तरीका है। अस्पताल में एचएमपीवी के मरीजों के लिए सामान्य और आइसोलेशन बेड की व्यवस्था है, और गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर से सुसज्जित आईसीयू बेड भी उपलब्ध हैं। नमूनों की जांच एम्स भोपाल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में की जाती है।

- डॉ. अजय सिंह, कार्यपालक निदेशक, एम्स भोपाल

डरने की जरूरत नहीं

जीएमसी भोपाल के वरिष्ठ श्वास रोग विशेषज्ञ डॉ. पराग शर्मा ने बताया कि 21 साल पहले, 2001 में, यह वायरस नीदरलैंड में पाया गया था। ठंड के मौसम में जितने सामान्य फ्लू के मामले होते हैं, उनमें से लगभग एक फीसदी मामले एचएमपीवी वायरस के होते हैं। यह वायरस फ्लू वायरस की तरह हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन ठंड के मौसम में ज्यादा सक्रिय हो जाता है।

डॉ. शर्मा ने कहा कि मरीज अगर लापरवाही न करें और समय पर इलाज कराएं, तो वे चार से पांच दिन में ठीक हो जाते हैं। हालांकि, जिन लोगों को सीपीओडी, टीबी, या फेफड़े से संबंधित गंभीर रोग हों, उन्हें अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

असिस्टेंट कमांडेंट की पत्नी नायब तहसीलदार के साथ साइबर फ्रॉड

जालसाज ने पति के क्रेडिट कार्ड की जानकारी ली, 2.64 लाख उड़ाए

भोपाल (नप्र)। भोपाल में नए साल की पार्टी के लिए होटल ताज में बुकिंग कराने के दौरान एक नायब तहसीलदार साइबर ठगी का शिकार हो गईं। गूगल पर सर्च किए गए फर्जी नंबर से संपर्क करने के बाद उन्होंने अपने पति, सीआईएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट के क्रेडिट कार्ड की जानकारी साझा की, जिससे जालसाज ने 2.64 लाख रुपये उड़ा लिए।

मामले की शिकायत थाने में की गई। एक सप्ताह की जांच के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

शाहपुरा थाना प्रभारी लोकेश ठाकुर ने बताया कि अंकित दुबे सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर हैं और वर्तमान में उनकी पोस्टिंग छिंदवाड़ा जिले में है। उनकी पत्नी नायब तहसीलदार हैं। वह रोहित नगर, शाहपुरा में परिवार के साथ रहती हैं।

31 दिसंबर को उन्हें परिवार के साथ नए साल की पार्टी के लिए होटल ताज जाना था। उनके पास होटल ताज का कोई संपर्क नंबर नहीं था, इसलिए उन्होंने गूगल के जरिए होटल का नंबर खोजा।

कम टिकट बचे होने का झांसा दिया था- पहले ही नंबर पर जो होटल ताज की वेबसाइट दिखी, उसे क्लिक करके उन्होंने दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल किया। कॉल रिसीव करने वाले व्यक्ति ने कहा कि बहुत कम टिकट बचे हुए हैं और जल्द से जल्द बुकिंग करनी होगी। जब नायब तहसीलदार ने बुकिंग के तरीके के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि वे क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान करेंगी।

पति से पूछा ओटीपी

नायब तहसीलदार ने भुगतान के लिए अपने पति अंकित दुबे के क्रेडिट कार्ड की डिटेल कॉल करने वाले के साथ साझा कर दी। इसके बाद कॉल करने वाले ने एक ओटीपी भेजा, जो दुबे के मोबाइल पर आया। नायब तहसीलदार ने अपने पति को कॉल कर ओटीपी पूछा और वह ओटीपी कॉल करने वाले को बता दिया। भरोसा जीतने के लिए जालसाज ने पहले 102 रुपये भेजे।

दूसरी बार में खाता खाली किया

दूसरी बार में जालसाज ने क्रेडिट कार्ड से 2.64 लाख रुपये निकाल लिए। बड़ी रकम निकलने का मैसेज आते ही दुबे को ठगी का एहसास हुआ। उन्होंने होटल ताज से संपर्क किया, तो पता चला कि उनके टिकट की कोई बुकिंग नहीं हुई है और वेबसाइट व मोबाइल नंबर होटल ताज का नहीं था।

मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश जारी

दुबे ने पहले अपने स्तर पर जालसाज का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। एक सप्ताह बाद उन्होंने शाहपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दुबे की शिकायत पर मोबाइल नंबर 9343287665 के धारक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। बैंक खातों की डिटेल के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है।

भोपाल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का समागम

- **आरजे रौनक, प्रियंक कानूनगो समेत कई दिग्गज दिखेंगे, प्रदेश के 300 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स भी आयेंगे**

भोपाल (नप्र)। भोपाल में आगामी 16 जनवरी को सोशल इन्फ्लुएंसर्स मीट कार्यक्रम होने जा रहा है। विश्व संवाद केंद्र मध्यप्रदेश के आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर के जाने माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का समागम होगा, जो सोशल मीडिया के प्रभाव और ताकत

पर चर्चा करेंगे। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की संभावनाओं पर भी अपने विचार रखेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश के 300 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स भी हिस्सा लेंगे।

समाज और डिजिटल मीडिया के बीच पुल बनाने का काम करेगा कार्यक्रम- कार्यक्रम के आयोजकों का कहना है कि इन्फ्लुएंसर्स का यह समागम समाज और डिजिटल मीडिया के बीच पुल बनाने का काम करेगा। कार्यक्रम प्रेरणादायक होने के साथ सोशल मीडिया के सही दिशा में इस्तेमाल के लिए भी जागरूकता बढ़ाएगा।

ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हिस्सा लेंगे

इस कार्यक्रम में देश की जानी-मानी हस्तियां वक्ता के तौर पर हिस्सा लेंगी। इनमें सोशल मीडिया हेंडल एक्स पर सामाजिक मुद्दे उठाने वाले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत सरकार के सदस्य प्रियंक कानूनगो, अपने अनूठे अंदाज के लिए मशहूर आरजे रौनक, ऑप इंडिया से जुड़ी नूपुर जे शर्मा और प्रश्नम के संस्थापक प्रवीण चतुर्वेदी समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल है।

बिजली कंपनी का रोको-टोको अभियान

भोपाल (नप्र)। एम.पी. ट्रांसको (मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी) की ट्रांसमिशन लाइनों के समीप चायनीज मांजे से पतंग उड़ाने के कारण संभावित दुर्घटना की आशंकाओं पर अंकुश लगाने और नागरिकों को सतर्क तथा सुरक्षित करने प्रदेश में एम.पी. ट्रांसको ने रोको-टोको अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिये एम.पी. ट्रांसको ने स्थानीय जिला प्रशासन से चायनीच मांझे के इस्तेमाल पर रोक तथा ट्रांसमिशन लाइनों के समीप के उन क्षेत्रों को संवेदनशील और खतरनाक घोषित करने के लिये अनुरोध किया है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आग्रह किया है की ट्रांसमिशन लाइनों के पास पतंग नहीं उड़ायें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बहुतायत पतंग उड़ाये जाने वाले संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिकों से व्यक्तिगत संपर्क किया जा रहा है। इसके अलावा पोस्टर बैनर एवं पब्लिक एनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से उन्हें सचेत एवं सतर्क किये जाने का अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही उपभोक्ताओं को विद्युत के अनावश्यक व्यवधान का सामना न करने पड़े। गत वर्ष राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, धार सहित कुछ स्थानों पर ट्रांसमिशन लाइनों में चायनीज मांजा के साथ पतंग फंसने की घटनाओं के बाद विद्युत व्यवधान हुआ था तथा पतंग उड़ाने वालों को भी नुकसान पहुँचा था। एम.पी. ट्रांसको के संवेदनशील प्रोटेक्शन सिस्टम के 100 प्रतिशत ऑपरेट होने से बड़ी जनधन हानि से बचा जा सका था।

क्यों घातक है चायनीज मांजा

चायनीज मांजा में कई तरह के केमिकल और धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जो डोरी को बिजली का अच्छा सुचालक बना देता है। यह संपर्क में आने से पतंग उड़ाने वाले के लिये घातक साबित होता है।

साथ ही ट्रांसमिशन लाइन में लिपटने से चीनी मांझे से क्षेत्र में विद्युत व्यवधान की आशंका भी रहती है।

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल में क्षेत्रीय रूपक महोत्सव का शुभारंभ

नाटकों के माध्यम से दर्शाई प्राचीन संस्कृति की झलक

भोपाल (नप्र)। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में आज (9 जनवरी 2025) से प्रारंभ हुआ क्षेत्रीय रूपक महोत्सव दर्शकों को भारतीय संस्कृति की विभिन्न रंगों से रूबरू करवा रहा है। इस महोत्सव में देशभर से आए दस नाट्य दल संस्कृत में नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें जयपुर, भीलवाड़ा, नागपुर, नासिक, दिल्ली, भोपाल सहित कई अन्य स्थानों के दल शामिल हैं। महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक प्रो. रमाकांत पांडेय ने किया।

उद्घाटन समारोह में आए कई प्रतिष्ठित अतिथि- कार्यक्रम के संरक्षक प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी (कुल गुरु, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली) हैं। इस महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक प्रो. रमाकांत पांडेय ने किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रो. राधावल्लभ त्रिपाठी(पूर्व कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली) उपस्थित थे। अन्य प्रमुख अतिथियों में प्रो. सदाशिव कुमार

द्विवेदी (निदेशक, भारत अध्ययन केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी) और प्रो. नीलाभ तिवारी (सह निदेशक, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल) शामिल थे।

संस्कृत नाट्य का महत्व और समकालीन मुद्दों पर चर्चा- प्रो. नीलाभ तिवारी ने उद्घाटन सत्र में कहा कि भारत एक विविध संस्कृतियों का देश है और इस महोत्सव में दर्शकों को इसकी झलक मिलेगी। वहीं प्रो. राधावल्लभ त्रिपाठी ने नाटकों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि नाट्य जीवन के चारों पुरुषार्थों (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) को प्राप्त करने का साधन है।

नाटकों में समकालीन मुद्दों का सजीव चित्रण- महोत्सव के पहले दिन कई महत्वपूर्ण नाटक प्रस्तुत किए गए। इनमें से एक नाटक 'मंत्रदानम' में एक दस्यु के सज्जन पुरुष बनने की कहानी दिखाई गई, तो वहीं 'धारित्रीपतिनिवार्चन' ने कन्या के लिए सुयोग्य वर का चयन करने की समस्या को मंच पर जीवंत किया। 'दीपदानम' नाटक में राजस्थान के गौरव को प्रदर्शित करते हुए पन्नाधाय के राज्य के प्रति समर्पण की भावनाएं व्यक्त की गई। 'मंजुला' नाटक ने नारी सम्मान और उत्थान की बात की, जबकि 'महिममयभारतम' ने देश की नदियों के महात्म्य का वर्णन किया।

इन सभी नाटकों ने दर्शाया कि संस्कृत नाट्य केवल अतीत की परंपराओं को ही नहीं, बल्कि समकालीन समाज की समस्याओं और आदर्शों को भी उजागर करते हैं। इस महोत्सव के माध्यम से संस्कृत नाटकों का पुनरुद्धार और जनमानस में उनकी प्रासंगिकता को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है।

संपादकीय

दिल्ली विस चुनाव 'आप' की साख दांव पर

दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ देश की दिलचस्पी इस बात में है कि आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चौथी बार सत्ता में लौट पाते हैं या नहीं। इस चुनाव में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी भी आप से सत्ता छीनने की हर संभव कोशिश कर रही है, इसके बाद भी यह कहना मुश्किल है कि दिल्लीवासियों के मन से आप प्रेम कम हो जाएगा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक यह जरूर मान रहे हैं कि पिछले दो विस चुनावों के मुकाबले इस बार आप व भाजपा में कांटे की टक्कर होती लग रही है। इस बात का संकेत इसी से मिल गया कि चुनाव घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को 'आप दा' बताते हुए हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि आप अपनी सत्ता को बचाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने में संकोच नहीं कर रही है, जिसमें महिलाओं को सम्मान निधि, मंदिरों के पुजारियों और गुरूद्वारों के ग्रंथियों को 18 हजार रू. मानदेय और दिल्ली में जाट आरक्षण लागू करना आदि शामिल है। दूसरी तरफ भाजपा खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल को भ्रष्ट साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस चुनाव में विपक्षी पार्टियों का गठबंधन भी पूरी तरह टूट गया है। दिल्ली में हाशिए पर पड़ी कांग्रेस भी अपनी गारंटियों के साथ राजनीतिक संजीवनी पाने का भरपूर प्रयास कर रही है। यू दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश है और वहां की सरकार अर्द्ध स्वायत्त सरकार है, लेकिन चूंकि दिल्ली देश की राजधानी भी है, इसलिए दिल्ली प्रदेश पर कब्जा करने और कब्जा कायम रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल उनकी गिरफ्तारी को लेकर सहानुभूति वोट बटोरने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन इसका फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में भी नहीं मिल सका था। ऐसे में उन्होंने रेवड़ी कल्चर के विस्तार की इंतिहा कर दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि वो इस दफा दिल्ली की एक सीट से ही लड़ेंगे। उधर भाजपा और कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ दमदार उम्मीदवार उतारकर संदेश दे दिया है कि केजरीवाल की जीत इस बार आसान नहीं होगी। इसमें दो राय नहीं कि 2013 में अन्ना आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी ने उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार हिस्सा लिया और 70 में से 28 सीटें जीत लीं।

तब कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए आप की सरकार को पहले समर्थन दिया और बाद में वापस ले लिया। इसके बाद आप ने ईमानदार पार्टी होने का प्रचार कर 2015 और 2020 के विस चुनावों में इकतरफा जीत दर्ज की। दिल्लीवासी लोकसभा में इकतरफा बीजेपी को जिताते हैं तो विधानसभा चुनाव में यही वोट आप को चला जाता है। मतलब जहां लोकसभा में जीतना जहां आप के लिए टेढ़ी खीर है, वहीं विस चुनाव जीतना भाजपा के लिए बेहद मुश्किल है। भाजपा की सारी उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं कि अब आप के ईमानदार और काम करने वाली सरकार के दावों की कलई खुल चुकी है। हालांकि जमीनी स्तर पर ऐसा लगता नहीं है। भाजपा का सत्ता में आना तभी संभव है, जब उसके पक्ष में कोई लहर चले। वरना इस बार भाजपा की कुछ सीटें जरूर बढ़ सकती है, लेकिन पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए, यह अभी भी दूर की कौड़ी लगती है। इसकी एक वजह आम दिल्लीवासियों के मन में आप के प्रति लगाव और राज्य सरकार द्वारा किए गए काम भी हैं। ऐसे में दिल्ली के लोगों का आप से मोहभंग हो गया है, ऐसा मान लेना गलत होगा।

नजरिया

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक भारत के राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफेसर हैं।

मानवाधिकार संरक्षण का नया रोडमैप तैयार करने की चुनौती

21वीं सदी के 25वें वर्ष के सफ़र में हम सभी सम्मिलित हैं। ऐसे समय में न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जिम्मेदारी दी गयी है। उन्हें 21 दिसंबर 2024 को भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा नियुक्त किया गया। पूरा भारत जानता है कि उनके पास 40 वर्ष से अधिक न्याय-प्रणाली के विविध अनुभव हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन ने पद संभाला है। 30 जून, 1958 को तमिलनाडु के मन्नारगुडी में जन्मे न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन सर्वोच्च न्यायालय के एक प्रतिष्ठित पूर्व न्यायाधीश हैं। जब सन् 1993 में आयोग के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा बने थे उन दिनों भारत की स्थितियां कुछ और थीं। भारत बस अपने उदारवादी रवैये को अपनाकर आर्थिक तंगी से उबरा था। आज की परिस्थिति बहुत अलग है। आज़ भारत के लिए यदि उसकी बड़ी जनसंख्या ताकत के रूप में देखी जा रही है तो वह चुनौती के रूप में भी परिभाषित की जा रही है। जीवन जीने के यत्न में मनुष्य की गरिमा, सुरक्षा, स्वतंत्रता, बंधुता और बुनियादी ज़रूरतें पूर्ण करने की चुनौती सरकार के पास भी है। मानव अधिकारों की सुरक्षा तो मनुष्य के समग्र उन्नति व आनंद के विषय हैं।

21वीं सदी के 25वें वर्ष के सफ़र में हम सभी सम्मिलित हैं। ऐसे समय में न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जिम्मेदारी दी गयी है। उन्हें 21 दिसंबर 2024 को भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा नियुक्त किया गया। पूरा भारत जानता है कि उनके पास 40 वर्ष से अधिक न्याय-प्रणाली के विविध अनुभव अनुभव हैं। भारतीय संविधान में उनकी गहरी आस्था है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद कॉलेज, चेन्नई से रसायन विज्ञान में स्नातक किया है। कानून की पढ़ाई उनकी मद्रास लॉ कॉलेज से हुई है। 16 फरवरी, 1983 को बार के सदस्य के रूप में वह नामांकित हुए, तब से लगातार वह भारत के न्याय-व्यवस्था से भारतीय जनमानस को लाभान्वित करने में संलग्न हैं। न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन ने मद्रास उच्च न्यायालय में लगभग 23 वर्षों तक वकालत की। 31 जुलाई 2006 को उन्हें मद्रास हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 9 नवंबर 2009 को वे स्थायी जज के रूप में स्थापित हुए। ऐसा माना जाता है कि उनके स्वयं के अनुरोध पर हैदराबाद के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। 27 अप्रैल, 2016 से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए विभाजन और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय के निर्माण के बाद, उन्होंने 1 जनवरी से हैदराबाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दी। 22 जून, 2019 को न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। 23 सितंबर, 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए जहाँ वे सेवानिवृत्ति तक कार्य किए। न्यायिक सेवा में मद्रास उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायायलय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक की उनकी निरंतर प्रगति उनके सुचितापूर्ण बहुमूल्य देशभक्ति की मिसालें हैं। उनके पूर्ववर्ती कार्य जिसमें सेवा कानून, मद्रास उच्च न्यायालय, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, उपभोक्ता मंच और दीवानी अदालतों दिए गए योगदान अपनी एक नई लंबी लकीर खींचते हैं। सबसे अहम् बात भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। वह 102 मामलों में निर्णय लिखने के बाद 29 जून, 2023 को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए, जिसमें 2016 की नोटबंदी नीति जैसे ऐतिहासिक मामले और रिश्वत के मामलों में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की वैधता से जुड़े मामले शामिल थे।

ऐसे अनुभवी व्यक्तित्व के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जिम्मेवारी राष्ट्रपति ने सौंपी है तो निश्चय ही इसके साथ भारत की एक सौ चालीस करोड़ जनमानस की अपनी उम्मीदें भी हैं। आज भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए सूचना तकनीकी और सूचना संजाल की उपस्थिति में सबकी गरिमा सुनिश्चित करना आसान हो गया है। बहुत ही ज़ल्दी से देश के एक कोने से दूसरे कोने संपर्क साधकर मानव अधिकारों के संवर्धन व संरक्षण के लिए कार्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इतनी व्यवस्थाओं के बीच अब मानव अधिकारों के संरक्षण से वंचित समाज भारत में रहे, यह एक शर्मनाक स्थिति मानी जाएगी। इसलिए नए अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन का नेतृत्व भारतीय जन के लिए यदि सुरक्षा कवच के रूप में छा जाए तो निश्चय ही भात में मानव अधिकारों के लिए कुछ विशेष देखा व सुना जा सकेगा।

यद्यपि भारत के लिए आज चुनौतियाँ नई तरीके की हैं। भारत में दलित, पिछड़े, आदिवासीजन, एलजीबीटीआईक्यू समाज और उसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांगजन सबके गरिमा की सुरक्षा के सवाल हैं तो इस देश को जलवायु परिवर्तन व एसडीजी-2030 के लक्ष्य की भी चुनौती को स्वीकार करने की आवश्यकता है। जेलों में रह रहे कैदी, ठेले-रिक्से से जीवन-यापन कर रहे श्रमिक, कामकाजी लोग और जरूरतमंद सबको उम्मीदें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से है और उसके नेतृत्व से है। नए अध्यक्ष के समक्ष यह चुनौती, चुनौती नहीं है अपितु यह अवसर है उनके लिए व उनके सान्निध्य में मानव अधिकार संरक्षकों के लिए कि वे निष्ठापूर्वक इन चुनौतियों से निपटकर एक गौरवशाली गरिमामय भारतीय समाज की तस्वीर दुनिया में प्रस्तुत करें।

भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व मंच पर और भारतीय भूभाग पर निरंतर यह आह्वान किया है भारतीयों से और प्रवासी भारतीयों से कि हमें 2050 तक विकसित भारत बनाना है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग व न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन के नेतृत्व को यह अब ध्यान रखना होगा कि हम भारत के सभी जन तक पहुंचें और उनकी सम्पूर्ण विकास, उन्नति व आनंद के लिए अवसर प्रदान करें। एक सशक्त मानवाधिकार संपन्न भारतीय राष्ट्र ही विकसित भारत का पैमाना बनेगा। यदि कोई पीछे छुट जाएगा तो देश पीछे रह जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सबसे अच्छी बात यह रही है कि उसने स्वत: संज्ञान के मामले में सक्रियता दिखाई है। यह एक नया और विशिष्ट न्याय की पहुँच बनाने का माध्यम बना है लेकिन अब आयोग को इसके विस्तार के लिए रणनीति बनानी होगी जिससे जो सूचनाएं पहुँच से बाहर रह जाती हैं, वे भी आयोग के चिंता का विषय बनें। जैसा कि न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन के बारे में ऐसा माना जाता है कि वह खुद व्यक्तियों के बीच अधिकारों के पालन और आनंद को सुरक्षित करने के लिए राज्य पर एक सकारात्मक दायित्व के हिमायती रहे हैं, उनसे भारत की जनता की उम्मीदें इसलिए ज्यादा बढ़ गयी हैं और जनता को यह विश्वास भी है कि न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन उनके लिए सदैव तत्पर रहेंगे।

पूर्व के अनुभव निश्चय ही एक सच्चे व सजग व्यक्तित्व को अपना नया रोडमैप तैयार करने में सहयोगी साबित होते हैं। न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन ने वैयक्तिक जीवन में बहुत ही सरल, विनम्र, दयालु, करुणामय छवि अपनी बनायीं है। उनकी चिंता व चिंतन ही अब भारत के लोगों के लिए नए प्रतिमान बनेंगे। अब उन्हें सार्वभौमिक सतत मूल्यों को भारतीय जनमानस में जागृत भी करना है और एक स्वस्थ, समृद्ध व गरिममय समाज का विकास भी करना है। संविधान लागू होने की 75 वर्ष बीत जाने के बाद देश के सभी नागरिकों को नए तरीके से तैयार करना है ताकि वे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र के साथ जिएं और भारत की वैश्विक उपस्थिति को ताकतवर बनाएं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने निरंतर गनहरि में ए प्लस ग्रेड के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करता रहा है, उस मानक को बनाये रखना भी ज़रूरी होगा। जैसा कि नए अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन अपने पहले संबोधन में मानव अधिकारों को महत्व देने और उनका पालन करने की भारत की प्राचीन परंपरा पर प्रकाश डाला है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मानव अधिकार भारत के सांस्कृतिक ताने-बाने में गहराई से अंतर्निहित हैं। मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। यह बताता है कि आयोग के साथ सभी नागरिकों को नए रचनात्मक सुअवसर मिलेंगे, यह तय है।

मुद्दा

रमेश सर्राफ धमोरा

लेखक पत्रकार हैं।

आत्महत्याओं की रोक के लिए ठोस पहल की दरकार

भारत में आए दिन आत्महत्या की घटनाएं घटित होती रहती है। यहां हर चार मिनट में एक आत्महत्या की जाती है। यहां शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता होगा जब किसी न किसी इलाके से गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, कर्ज जैसी तमाम आर्थिक तथा अन्य सामाजिक दुश्वारियों से परेशान लोगों के आत्महत्या करने की खबरें न आती हों। आत्महत्या करना सभ्य समाज के माथे पर एक कलंक के समान है। आत्महत्या में व्यक्ति स्वयं को दंडित करते हुए अपनी जान दे देता है। ऐसा घिनोना कार्य कोई व्यक्ति तभी करता है जब वह चारों तरफ से निराश हो जाता है।

आत्महत्या करने का सबसे बड़ा कारण आर्थिक पक्ष को माना जाता है। उसके बाद मानसिक, पारिवारिक व अन्य बहुत से कारण हो सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर होने पर व्यक्ति स्वयं को गिरा हुआ महसूस करता है और अंत में वह आत्महत्या करने जैसा घिनौना कदम उठा लेता है। हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि बहुत से परिवारों ने आर्थिक कर्म से सामूहिक आत्महत्या कर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। बहुत से किसान अपना खेती का कर्ज नहीं चुका पाने के कारण भी बड़ी संख्या में आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कानून तो बना दिया मगर उसका प्रभाव समाज पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेम में असफल होने पर भी बड़ी संख्या में नवयुवक युवतियां आत्महत्या कर अपने जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं।

आंकड़ों की दृष्टि से भारत आत्महत्याओं के मामले में दुनिया में सिरमौर बनता जा रहा है। आत्महत्या रोकने की दिशा में अब तक सरकारी स्तर पर जितने भी प्रयास हुए हैं वह सब नाकाम साबित हुए हैं। सरकारी आंकड़ों में जितनी आत्महत्या की संख्या दर्शायी जाती है उससे कई गुना अधिक लोग आत्महत्या कर अपनी जान गंवा रहे हैं। मगर आत्महत्या की घटनाओं को रोकने की कोई सार्थक पहल नहीं हो पाई है। खेती के लिए लिया गया कर्ज़ नहीं चुका पाने के कारण भी बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मगर सरकारी बैंकों, साहूकारों के कर्ज से परेशान किसान आज भी आत्महत्या कर रहें हैं। उन्हें रोकने की दिशा में भी सरकार ने कोई विशेष पहल नहीं की है। बैंक आज भी किसानों से जबरदस्ती कर्ज वसूली के लिए उनकी जमीने नीलाम कर रहे हैं। इसी के चलते किसान मजबूर होकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं।

भारत में आत्महत्या एक प्रमुख समस्या है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 171,000 आत्महत्याएं की गईं थी जो 2021 की तुलना में 4.2 प्रतिशत अधिक थी । प्रति एक लाख की जनसंख्या पर आत्महत्या की दर 2022 में बढ़कर 12.4 हो गई जो आंकड़ो के हिसाब से सर्वोच्च थी। 2022 के दौरान आत्महत्याओं में 2018 की तुलना में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई और भारत में दुनिया में सबसे अधिक आत्महत्याएं हुईं। वैश्विक आत्महत्या मौतों में भारत के आंकड़े 1990 में 25.3 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में महिलाओं में 36.6 प्रतिशत और पुरुषों में 18.7 प्रतिशत से बढ़कर 24.3 प्रतिशत हो गये। 2016 में 15-29 वर्ष और 15-39 वर्ष के आयु समूहों में आत्महत्या मृत्यु का सबसे आम कारण था। दैनिक वेतन भोगी लोग आत्महत्या पीड़ितों का 26 प्रतिशत हिस्सा थे। जो आत्महत्या के आंकड़ों में सबसे बड़ा समूह था।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में राज्यों में सबसे अधिक आत्महत्याएं महाराष्ट्र (22,746) में हुईं। इसके बाद तमिलनाडु में 19,834 और मध्य प्रदेश में 15,386 आत्महत्याएं हुईं। चार राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल को मिलाकर देश में हुयी कुल आत्महत्याओं में से लगभग आधी उक्त प्रदेशों में हुयी थी। नागालैंड में केवल 41 आत्महत्याएं हुईं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में 2017 से 2019 के दौरान भारत में लगभग आधी आत्महत्याएं हुयी हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में सबसे अधिक आत्महत्याएं हुईं, उसके बाद पुडुचेरी का स्थान रहा। बिहार और पंजाब में 2018 की तुलना में 2019 में आत्महत्याओं के प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुयी थी।

एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले पांच सालों में आत्महत्या की घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ दिखता है। 2017 में देश में 1,29,887 आत्महत्याओं की मामले रिकॉर्ड किए गए थे। तब आत्महत्या दर 9.9 प्रतिशत थी। आत्महत्या दर प्रति लाख आबादी पर होने वाली आत्महत्या की घटनाओं को दर्शाता है। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक देश में प्रति लाख 9.9 आत्महत्या की घटनाएं दर्ज की गईं थी। 2018 में आत्महत्या दर में इजाफा हुआ और ये बढ़ कर 10.2 पर पहुंच गयी थ। तब देश में 1,34,516 आत्महत्या के मामले दर्ज हुए थे। 2019 में कुल 1,39,123 लोगों ने तो 2020 में ये संख्या बढ़कर 1,53,052 हो गई थी। 2021 में आत्महत्या के 1,64,033 मामले हुये थे।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तुलनात्मक आंकड़े बताते हैं कि भारत में आत्महत्या की दर विश्व आत्महत्या दर के मुकाबले बढ़ी है। भारत में पिछले दो दशकों की आत्महत्या दर में एक लाख लोगों पर 2.5 फीसद की वृद्धि हुई है। आज भारत में 37.8 फीसद आत्महत्या करने वाले लोग 30 वर्ष से भी कम उम्र के हैं। दूसरी ओर 44 वर्ष तक के लोगों में आत्महत्या की दर 71 फीसद तक बढ़ी है। 2018 में पारित हुए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के तहत भारत में आत्महत्या के अपराधीकरण का कानून खत्म करते हुए मानसिक बीमरियों से जूझ रहे लोगों को मुफ्त मदद का प्रावधान किया गया है। इस नए कानून के तहत आत्महत्या का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को मदद पहुंचाना, इलाज करवाना और पुनर्वास देना सरकार की जिम्मेदारी होगी।

भारत के साथ-साथ पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ से जूझ रहे लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस मामले में अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोई ठोस बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन विश्व के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों पर तुरंत संज्ञान लेने की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल लगभग आठ लाख लोग आत्महत्या करते हैं। जिनमें से 21 फीसदी आत्महत्याएं भारत में होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में सरकारों को सलाह दी गई है कि आत्महत्या का मीडिया ट्रायल नहीं हो। देश में अल्कोहल को लेकर ठोस नीति बनाई जाए। आत्महत्या के संसाधनों पर रोक लगाते हुए आत्महत्या के प्रयास करने वालों की उचित देखभाल की जाए।

आत्महत्या जैसे मामलों को रोकने के लिए समाज के हर एक जिम्मेदार व्यक्ति को सामने आने की जरूरत है। जिससे ज्यादा-से-ज्यादा लोग इस बात से जागरूक हो सकें और आत्महत्या जैसे मामलों में कमी लाई जा सके। सभी को इस बात को समझने की जरूरत है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिन्दगी में तनाव की स्थिति कभी कम तो कभी ज्यादा बनी रहती है। परंतु इसका समाधान अपनी जिन्दगी को समाप्त कर लेना नहीं हैं। जानबूझकर खुद को मारना आत्महत्या या 'फेलो डे से' के रूप में जाना जाता है। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 309 आत्महत्या से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी आत्महत्या का प्रयास करेगा और इस तरह के अपराध को अंजाम देगा उसे एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि आत्महत्या के मामलों के अध्ययन के बाद सरकार और गैर-सामाजिक संगठनों को मिल कर एक ठोस पहल करनी होगी। इसके लिए जागरुकता अभियान चलाना होगा। ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने की ठोस रणनीति के बिना देश में बढ़ती आत्महत्यों पर रोक लगाना मुश्किल होगा। सरकार को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आर्थिक-सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों की गहराई से पड़ताल करनी चाहिये। साथ ही ऐसे उपाय करे कि लोग अपनी जीवनलीला समाप्त करने का विचार ही दिमाग में न लाए।

संवेदनाओं से दूर होती सरकारें

अभिव्यक्ति

अदिति सिंह भदौरिया

लेखक व्यंग्यकार हैं।

जब संवेदना मनुष्य के स्वभाव का मूल आधार है। जब तक हम मनुष्य बनकर अपने किसी भी फैसले का निर्णय नहीं लेते तब तक हमारे लिए गए निर्णय मानव कल्याण के लिए जरूरी नहीं लगते। आम जन-मानस अपने रोज़ के झंझटों में इतना घिरा रहता है कि उसे और कुछ ध्यान नहीं होता। इसलिए वह अपने देश को और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए किसी भी राजनैतिक पार्टी को वोद देकर उनपर अपना विश्वास दिखाता है। इसलिए हर राजनैतिक पार्टी और राजनेता का यह नैतिक दायित्व है कि वह कोई भी निर्णय लेने से पहले उन आम लोगों के बारे में ज़रूर सोंचे जिन्होंने उन्हें ख़ास बनाया है। वह मनुष्य है कोई कचरा नहीं जिसे कभी भी कहीं भी मिटाया या जलाया जा सकें।

देखने वाली बात यह है कि ऐसा कौन सा नेता सोचता है? जवाब हम सब जानते है कि ज़यादातर नेता नहीं सोचते। हाल ही में एक बेहद ज़रूरी निर्णय लिया गया कि भोपाल गैस त्रासदी से उत्पन हुए कचरे को कहाँ जलाया जाए? तो सरकार द्वारा निर्णय लिया गया उसे पीथमपुर में जलाया जाए। यह एक बेहद ज़रूरी निर्यय है। पर दु:ख की बात यह है जिस त्रासदी की झलक आज भी भोपाल के वासियों में देखने को मिलती है, हम उस त्रासदी को कैसे भूल गए और एक नई त्रासदी की तैयारी में जुट गए है। हमें यह सोचना चाहिए कि जिसकी गैस के लीक मात्र होने से कई ज़िन्दगियाँ बर्बाद हो गई। उसके कचरे से कितना कुप्रभाव पड़ेगा, यह सोचना निर्णय लेने वालों के मन में उठते प्रश्नों में से अहम प्रश्न होना चाहिए था। पीथमपुरा किसी सुनसान मरुस्थल का नाम नहीं है बल्कि एक रिहायशी एरिया है। जिसके साथ ही, इंदौर और इंदौर के पास ही देवास और उज्जैन है। आज जब 40 साल बाद भी हम उस त्रासदी के कहर से छूट नहीं पाए है तो क्या आने वाले 40 साल को फिर से उस त्रासदी के लिए तैयार कर रहे है?

प्रश्न यह भी उठता है कि जब देश के किसी भी कार्य को करने के लिए टीम नियुक्त की जाती है, तब क्या उस टीम को अपने कार्य के प्रभाव और दुष्प्रभाव के बारे में पता नहीं होता या राजनैतिक दल उन पर ध्यान नहीं देते?

क्यों किसी एक कार्य को करने की ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार लेती है फिर उसी कार्य के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीमकोर्ट के निर्णय पर निर्भर रहना पड़ता है? आम जनता ने सरकार को अपने निर्णय लेने का दायित्व दिया है या किसी कोर्ट को अपनी ज़िम्मेदारी सौपी है?

मीडिया को फटकार लगा देना या यह कह देने मात्र से कि कोई खतरा नहीं है, क्या सच में खतरा खत्म हो जाता है?

उस त्रासदी की जिमेदारी आज की केंद्र सरकार की नहीं है, उस समय की सरकार की है। इस बात से हम भली-भांति अवगत है। इसलिए तो आज की सरकार पर अपना विश्वास जताया है कि यह सरकार आम जनता की आवाज़ सुनेगी, पर क्या ऐसा हो रहा है? उस समय की सरकार ने वारेन एंडरसन को देश से जाने दिया। लगभग 15000 लोगों की तत्काल मौत होने और बड़ी संख्या में लोगों का बीमारियों का शिकार बनने से आज तक भी उस गैस के लीक होने से उस इलाके को प्रभावी इलाका माना जाता है। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली (MIC) नामक जहरीली गैस के दुष्परिणाम आज भी देखने को मिलते है। किसी भी युद्ध क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के मुकाबले भोपाल त्रासदी को गिना जाता है। क्या इसका कचरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा, इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है।

पीथमपुरा में सेक्टर नंबर 2 के जिस इलाके में यह कचरा जलाया जाएगा , वह एक पहाडी पर मौजूद है। जो धार जिले में आती है और उसकी तलहटी इंदौर जिले में आती है। करीब 10 वर्ष पूर्व इस कचरे को जलाने को लेकर यहाँ यूनियन कार्बाइट का परीक्षण हो चुका है। हालाकि रिपोर्ट कहती है करीब छह परीक्षण को ई बहुत सफल नहीं रहे, इसके बावजूद कचरे को जलाने के बारे में यहाँ सोचा जा रहा है तो यह चिंता का विषय है।

सरकारें आती- जाती रहती है, पर संवेदनाओं का खत्म होना विनाश का सूचक है। यह वही संवेदनहीनता है जो उस समय की सरकार ने दिखाई थी। क्या किसी भी मरुस्थल की धरती उस कचरे को अपने भीतर समाने में सक्षम नहीं है, जिसको मानव मूल्यों की समाधी बनाने के लिए सरकार तत्पर दिखाई दे रही है।

हम यानि आम जनता सरकार से उम्मीद रखती है कि वह अपने परिवार जन की तरह हमारी देखभाल करें। आशा करती हूँ कि सरकार के निर्णय बदलें तो आम जनता के भले के लिए बदलें ना कि विश्वास का बलिदान देकर इतिहास के एक और काले अध्याय की स्याही बनकर ना उभरें।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा

लेखक व्यंग्यकार हैं।

सपनों की धरती पर लाठी का राज

उस दिन सूरज भी अपनी किरणों के साथ धरने पर बैठा था। उसका कहना था, 'इतनी बेईमानी देखना मेरे बस की बात नहीं।' वहीं, धरने पर बैठे छात्र किताबें लेकर आए थे। किताबें, जो अब सिर्फ कागज के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं थीं। उनमें लिखे सवाल हवा में तैर रहे थे, मानो पूछ रहे हों, 'क्या हमारी कोई अहमियत है?'

सरकार की तरफ से पहले तो चाय-पानी का इंतजाम आया, फिर पुलिस का। छात्र बैठे रहे, पुलिस खड़ी रही। कुछ देर बाद, पुलिस ने अपने 'लाठी-प्रणाम' से छात्रों को सलामी दी। हर लाठी की चोट के साथ सरकार की नीयत का 'नोटिस' छात्रों के शरीर पर लाल निशान बनाकर लिख दिया गया। लाठीचार्ज के बाद, अस्पतालों में छात्र भर्ती हुए। डॉक्टर भी कुछ निराश लग रहे थे। एक डॉक्टर ने कहा, 'भाई, सरकार को तो नौकरी देनी नहीं है, लेकिन मरीज खूब दे रही है।' सरकार के प्रवक्ता ने प्रेस कांफ्रेंस बुलाई। उन्होंने कहा, 'छात्रों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हमने कार्रवाई की।' एक पत्रकार ने पूछा, 'छात्रों का क्या नुकसान हुआ?' प्रवक्ता बोले, 'वो तो उनकी पढ़ाई-लिखाई का ही नुकसान है। जब नौकरी नहीं है, तो पढ़ाई का क्या फायदा?'

धरना खत्म नहीं हुआ था। खून के निशान मिटाने वाले बयान टीवी पर आते रहे। 'यह लाठीचार्ज छात्रों की भलाई के लिए था। अब वे धरने पर बैठने की बजाय नौकरी ढूंढने जाएंगे।'

धरना स्थल पर एक नई बहस शुरू हो गई। एक छात्र बोला, 'सरकार कहती है, पैसा नहीं है। लेकिन मंत्री जी की नई गाड़ी में पैसे का कोई अभाव नहीं दिखा।' दूसरा छात्र हंसा और बोला, 'भाई, पैसा है, लेकिन हम पर खर्च करने के लिए नहीं। भ्रष्टाचार में इन्वेस्ट करने के लिए है।'

इधर, धरना स्थल पर कुछ बच्चे आ गए। उन्होंने पूछा, 'भाईया, आप लोग क्या कर रहे हो?' छात्रों ने जवाब दिया, 'हम नौकरी मांग रहे हैं।' बच्चों ने मासूमियत से कहा, 'तो पढ़ाई क्यों की?' यह सुनकर छात्रों के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई।

सरकार के मंत्री जी ने अगले दिन एक बयान दिया, 'हमने छात्रों के भविष्य के लिए बड़े कदम उठाए हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी है। अब वे अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढेंगे।' एक पत्रकार ने पूछा, 'और नौकरी?' मंत्री जी मुस्कुराए और बोले, 'अरे भाई, देश के युवा अब स्टार्टअप्स पर ध्यान दें। नौकरी मांगने से ज्यादा नौकरी देने की सोचें।'

धरना जारी था। लाठीचार्ज के बाद भी। छात्रों का कहना था, 'हम पढ़ाई करके बैठे हैं, पर सरकार के कानों तक यह बात पहुंचाने के लिए हमें चिल्लाना पड़ेगा।'

कुछ दिन बाद, धरने पर बैठे छात्रों में से एक ने एक कविता लिखी

खून बहा, मगर वादे नहीं बने, सरकार ने फिर से सपने छीने।
पढ़ाई की, मेहनतकी रात-दिन, मगर हमारी बातें, सुनता कौन?
धरने के पास से गुजरते लोग रुके। कुछ ने समर्थन दिया, तो
कुछ ने कहा,
'इतने सालों तक पढ़ाई की, अब धरने पर बैठने का वक्त है?' छात्रों ने
जवाब
दिया, 'पढ़ाई तो की, मगर नौकरी नहीं मिली। अब क्या करें?'
सरकार के पास पैसे थे, लेकिन छात्रों के भविष्य के लिए नहीं।
छात्र सवाल
पूछते रहे, जवाब मिलते रहे। और इस बीच, सूरज अपनी किरणों
को समेटते हुए
सोचने लगा, 'शायद कल की रोशनी इस अंधकार को मिटा सके।'
धरना समाप्त हुआ या नहीं, यह सवाल आज भी हवा में तैर रहा
है। छात्रों के सपनों का भविष्य कौन लिखेगा, यह सवाल अब भी
अनुत्तरित है। और सरकार? वह
अपने अगले बजट में नई योजनाओं की घोषणा करने में
व्यस्त है।

ज्ञान-महाकुंभ

प्रो. नीलिमा गुप्ता

(कुलपति, डॉ. हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर)

शिक्षा, संस्कृति एवं भारत बोध के समागम की पहल

'ज्ञान महाकुंभ' के माध्यम से भारतीय परंपरा को शिक्षा जगत में समाहित करने का एक अनूठा प्रयास प्रख्यात शैक्षिक संगठन 'शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास' द्वारा किया जा रहा है। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को आधार बनाकर भारतीय शिक्षा की पुर्नस्थापना हेतु 'ज्ञान महाकुंभ' का आयोजन 10 जनवरी से 10 फरवरी तक किया जा रहा है। इस महाकुंभ की संकल्पना है कि भारत केन्द्रित शिक्षा का एक अभियान चलाकर, सामूहिक रूप से भारत केन्द्रित शिक्षा की पुर्नस्थापना करने में सफल हों।

भारतीय सांस्कृतिक विरासत में मेले का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लाखों-करोड़ों की आस्था का प्रतीक कुंभ, मेले के रूप में प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, और उज्जैन में आयोजित कर उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि यहां स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। एक तरह से यह आत्मशुद्धि का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। यह मेला हिंदू धर्म की एकता और भारतीय सांस्कृतिक विकास का प्रतीक माना जाता है।

कुंभ मेले का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है। भारतीय ऋषि-मुनि नदियों के किनारे एकत्रित होकर धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में गंगा नदी के प्रति आस्था अक्षुण्ण है। यहाँ होने वाले अनुष्ठान का सांस्कृतिक महत्व है। इस वर्ष प्रयागराज संगम पर आयोजित होने वाला महाकुंभ 12 वर्ष के पश्चात हो रहा है। महत्वपूर्ण बात यह कि यह पूर्ण महाकुम्भ है, जो 144 साल बाद आयोजित हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति को अपने जीवन में केवल एक बार ही पूर्ण महाकुम्भ में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। प्रयागराज महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। प्रयागराज, गंगा, यमुना तथा सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है इसलिए इसका महत्त्व और अधिक बढ़ जाता है। आम भाषा में यह 'संगम स्नान' के नाम से संबोधित किया जाता है।

इस अवसर पर 'ज्ञान महाकुंभ' के माध्यम से भारतीय परंपरा को शिक्षा जगत में समाहित करने का एक अनूठा प्रयास प्रख्यात शैक्षिक संगठन 'शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास' द्वारा किया जा रहा है। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को आधार बनाकर

भारतीय शिक्षा की पुर्नस्थापना हेतु 'ज्ञान महाकुंभ' का आयोजन 10 जनवरी से 10 फरवरी तक किया जा रहा है।

इस महाकुंभ की संकल्पना है कि भारत केन्द्रित शिक्षा का एक अभियान चलाकर, सामूहिक रूप से भारत केन्द्रित शिक्षा की पुर्नस्थापना करने में सफल हों। इस आयोजन में 'हरित महाकुंभ' पर राष्ट्रीय सम्मेलन, 'एक राष्ट्र का नामः भारत' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी और 'भारतीय शिक्षाः राष्ट्रीय संकल्पना' पर विस्तृत राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं। इसमें देश भर के कुलपति, निदेशक, शिक्षाविद, आचार्य, शासन-प्रशासन एवं निजी शैक्षिक संस्थानों से जुड़े महानुभाव, शिक्षा जगत में उल्लेखनीय कार्य कर रहे संत-महात्मा, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे उद्योग जगत के सेवाभावी महानुभाव सम्मिलित होंगे।

ये सभी भारतीय शिक्षा की नींव को सशक्त करते हुए और एक नया रुप देकर भारतीय शिक्षा का पुर्ननिर्माण करने हेतु दिशा देने का प्रयास करेंगे। इस आयोजन में दिनों दिन बढ़ती निजी शिक्षा संस्थानों की भारतीय शिक्षा में भूमिका, छात्र, महिला तथा आचार्य सम्मेलन, शासन-प्रशासन की शिक्षा में भूमिका, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषा तथा शिक्षा से आत्मनिर्भरता जैसे ज्वलंत विषयों पर गहन चर्चा होगी। ज्ञान महाकुंभ एक अद्वितीय आयोजन है जो ज्ञान, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर केंद्रित है।

ज्ञान महाकुंभ का उद्देश्य ज्ञान का आदान-प्रदान, शिक्षा और सांस्कृतिक विकास, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के बीच संवाद तथा युवाओं को प्रेरित करके उन्हें ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ाना है। इस महाकुंभ में विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी, जिनमें व्याख्यान और सेमिनार, पैनल चर्चाएँ, कार्यशालाएँ, प्रदर्शनी और प्रदर्शन, तथा संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं। शिक्षा के भारतीयकरण, भारतीय ज्ञान परंपरा, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना, मूल्य शिक्षा, भाषा जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार-विमर्श इस आयोजन के केंद्र में होंगे।

यह महत्वपूर्ण आयोजन न केवल ज्ञान, शिक्षा और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देगा बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और विद्वानों के ज्ञान और अनुभवों का साझा मंच बनेगा। इस अनूठे आयोजन में सहभागी होकर हम भारतीय नागरिक, भारतीय संस्कृति तथा भारतीय शिक्षा से परिपूर्ण होकर एक नए भारत का निर्माण करने में अवश्य सफल होंगे। इस अवसर का हम अवश्य लाभ उठाएँ और भारतीय संस्कृति तथा भारतीय शिक्षा को जोड़ने हेतु ज्यादा संख्या में भाग लें।

दृष्टिकोण

ध्रुव शुक्ल

लेखक साहित्यकार हैं।

सनातन कोई राजनीतिक किस्सा नहीं है

संसार की प्रकृति... पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि... इन पांच तत्वों में बरत रही है। प्रत्येक संवत्सर के छह ऋतुकालों में ये पांचों तत्व आपस में मिलकर सबके जीवन के पोषण का इंतजाम करते हैं। हमें अग्नि से रूप का, वायु से स्पर्श का, जल से रस का, पृथ्वी से गंध का और आकाश से शब्द का अनुभव होता है। इनके आकर्षण में हम बंधते हैं। हम अभिव्यक्त होना चाहते हैं।

किसी ने हमारा नाम रख दिया कि हम हिन्दू हैं पर यह नाम हमारी पहचान नहीं है। हम तो उस सनातन सत्य में रहते आये हैं जहाँ जाति, वर्ण, कुल आदि गुण आधारित सामाजिक व्यवहार के लिए हैं। अभी मकर संक्रांति पर गंगाजल में होने वाले स्नान को देख लीजिए तो पता चलेगा कि पूज्यनीय शंकराचार्य और महामण्डलेश्वरों के साथ राजनीतिक रूप से विभाजित किये गये दलित, पिछड़े, सवर्ण सब एक साथ बिना किसी भेदभाव के डुबकी ले रहे होंगे। कुम्भ के मेले में कोई किसी की जात नहीं पूछता, वहाँ तो सदियों से ज्ञान बूझने की परंपरा रही है।

श्री रमण महर्षि कहते थे कि... ईश्वर नहीं है,तुम हो। अपने आपको जान लो तो फिर ईश्वर को पाने की झंझट से मुक्त हो जाओगे। वह तुम्हें मिला ही हुआ है। ...हमारी ज़िन्दगी की फिल्म हमारे ही भीतर चल रही है। हम ही इस फिल्म के निर्माता हैं। बाहर कोई हमारा दिग्दर्शक नहीं। हमारा शरीर ही हमारे जीवन का सिनेमा घर है। सब अपने आपको खुद ही रचते हैं। अपने आपको पहचान लेना ही सनातन धर्म है। यह पहचान होते ही नाम-रूप से परे उस अविनाशी का बोध होता है जो सब में समाया हुआ है।

संसार की प्रकृति.. पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि..- इन पांच तत्वों में बरत रही है। प्रत्येक संवत्सर के छह ऋतुकालों में ये पांचों तत्व आपस में मिलकर सबके जीवन के पोषण का इंतजाम करते हैं। हमें अग्नि से रूप का, वायु से स्पर्श का, जल से रस का, पृथ्वी से गंध का और आकाश से शब्द का अनुभव होता है। इनके आकर्षण में हम बंधते हैं। हम अभिव्यक्त होना चाहते हैं।

रूप-स्पर्श-रस-गंध-शब्द में हमारी सहज आसक्ति हुआ करती है और इसी आसक्ति के कारण अनगिनत कामनाएं हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं। प्रकृति के गुणों.. रज-सत्व और तमस के अनुसार कामनाएं पूरी होने और न होने की स्थिति हमारे ही स्वभाव से निर्धारित होती है। जो बहुत रजोगुणी होते हैं उनकी कामनाएं प्रबल होने से वे कई तरह की भाग-दौड़ करके, कैसे भी अपना हित साधन करते हैं। जिनका तमस गुण बहुत बढ़ा हुआ होता है वे आलस्य से भरे होने के कारण अपना हित साधन नहीं कर पाते, पराधीन होते जाते हैं। जो सत्व को पहचान लेते हैं वे रजो गुण और तमोगुण की अतियों से बचकर बीच का समत्व का मार्ग अपनाते हैं।

भारतीय ज्ञान का मूल उपदेश भी यही है कि केवल अपनी ज़रूरत का ही लो, बाकी शेष जीवन के लिए छोड़ दो। क्योंकि सबकी अनगिनत कामनाओं की पूर्ति जीवन में कभी संभव नहीं होती। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विघ्न आते ही रहते हैं। क्षिति-जल-पावक-गगन और समीर.. ये पांच तत्व सबके जीवन के साधन हैं। इनकी उन्नति करना और फिर इनसे अपना पोषण प्राप्त करके परस्पर आश्रय में सद्भावपूर्व जीवनयापन ही

सामुदायिक साध्य माना गया है। अकेली राज्य व्यवस्था इसे नहीं संभाल सकती। इसीलिए वह हमेशा विफल साबित होती है।

जन्म से मृत्यु के बीच सृजन, पालन और संहार का क्रम साफ दिखायी देता है। हमारी रचना होती है, हम पाले-पोसे जाते हैं और मरते हैं। अपने जीवन की रचना का हम इतना ही कारण जानते हैं कि संयोगवश हमारा जन्म होता है। हमारा पालन करने में ऋतुओं की भूमिका है। वही हमें अन्न, फल, वस्त्र देती हैं। हमारी प्रकृति ही हमें अपने स्वभाव के अनुरूप अपनी जिन्दगी की खेती करने के योग्य बनाती है।

जीवन को संतों ने करम की खेती कहा है .. जैसा बोओ, वैसा काटो। हम अपने जीवन में क्या बो रहे हैं, यह विचार हमें ही करना पड़ेगा। हमसे दूर कोई ईश्वर नहीं बैठा है जो हमारा स्वार्थ साध दे। परमार्थ का अर्थ केवल इतना है कि सब मिलकर प्रकृति के उन पांचों तत्वों को मैला न होने दें जो हमें अन्न-जल का प्रत्यक्ष वरदान दिए हुए हैं। हमारे जीवन के प्रति न्याय करने वाली वास्तविक पंचायत यही है। हमें विभाजित करके हमारी सत्ता हथयाने वाली झगड़ालू पार्लियामेण्ट नहीं।

प्रकृति सहित हम सबमें वह चेतना निवास करती है जो दीखती नहीं पर पूरा जीवन उसी से संचालित है। उस चेतना का निवास स्थान यह पूरा संसार है। वैश्विक चेतना के इस निवास स्थान को सहज-सुंदर बनाये और बचाये रखने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे जीवन जैसी होकर वह चेतना सगुण होकर हमें अपनाती है और जब हम अपनी मृत्यु होने पर संसार छोड़ते हैं तो वही चेतना निर्गुण हो जाती है। अगर कोई ईश्वर है तो वह हमें इसी विधि से मिला ही हुआ है।

हम गैरज़रूरी चीजों से भरे बाजार और पतनशील राजनीति में फंसे हुए हैं जो हमारे रजो गुण को ठगकर हमारी अनुपयोगी कामनाएं बढ़ाकर अपना स्वार्थ साध रहे हैं और हमारे तमस को उकसाकर हमें बेबस और असहाय जीवन जीने को विवश किया जा रहा है। इन दो अतियों के कारण जीवन में विषमता बढ़ती जा रही है। राजनीतिक निकाय हमारे जीवनयापन की व्यवस्था करने में विफल हो गये हैं। वे हमारी पगडण्डियों को मिटाकर न जाने किस दूर दुनिया की तृष्णा की सड़क पर हमें हांके चले जा रहे हैं? सनातन को कदम-कदम पर हमारी प्रतिभा का समर्थन चाहिए। वह हमारे विवेक की पगडण्डी पर हमारे साथ चलने को सदा राजी है। इस सनातन धर्म को कोई राजनीतिक निगम-मण्डल नहीं चाहिए। सारे राजनीतिक किस्से हमें परतंत्र बनाये रखने के लिए गढ़े जा रहे हैं।

विश्व हिंदी दिवस पर विशेष

प्रमोद दीक्षित मलय

लेखक शैक्षिक संवाद मंच के संस्थापक हैं।

विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली तीसरी भाषा है हिंदी

भाषा अभिव्यक्ति का सहज माध्यम है। भाषा दो व्यक्तियों, समुदायों और देशों के बीच परस्पर संपर्क-संवाद का सुगम सेतु है। भाषा व्यक्ति की पहचान है तो राष्ट्र का गर्व, गौरव और अस्मिता भी। बिन भाषा के व्यक्ति मूक है और राष्ट्र गूंगा है। भाषा है तो व्यापार है, जीवन के तमाम व्यवहार हैं और आदर-सत्कार भी। भाषा संबंध जोड़ती और रिश्ते गढ़ती है। भाषा निर्झर निर्मल नीर है तो हृदय की वेदना, कसक, पीर भी। भाषा है तो जीवन है और जीवन के इंद्रधनुषी रंग भी। खुशी की बात है कि भारत भाषाओं के मामले में समृद्ध है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम अनेकानेक भाषाएं अपनी रचनात्मकता से मां भारती का अर्चन-स्तवन कर रही हैं। यहां किसी भाषा का किसी से बैर भाव नहीं, वह परस्पर सखी-सहेली हैं। हिंदी भले ही संपूर्ण भारत में न बोली जाती हो पर समझी अवश्य जाती है। हिंदी राष्ट्रभाषा भले ही न हो किंतु राजकाज की भाषा है। 10 राज्यों ने हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया है जिनमें बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली आदि राज्य हैं। गुजरात, पश्चिम बंगाल और मिजोरम राज्यों में हिंदी द्वितीय राजाभाषा के रूप में समादृत है। वैश्वीकरण के दौर में हिंदी विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। हिंदी के प्रचार-प्रसार में 150 से अधिक संस्थाएं देश-विदेश में सक्रिय एवं साधनारत हैं। इस श्रृंखला में विश्व हिंदी सम्मेलन जैसे जागतिक आयोजन का स्मरण स्वाभाविक है जिसके करण 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाना आरम्भ हुआ है।

विश्व में हिंदी के प्रचार एवं प्रसार हेतु जन जागरूकता उत्पन्न करने तथा अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को प्रस्तुत करने हेतु सर्वप्रथम 10 जनवरी, 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आयोजन में 30 देशों से 122 से अधिक हिंदी प्रेमी प्रतिनिधि सम्मिलित हो हिंदी के प्रचार-प्रसार की नीति

बना आगे बढ़े थे। विश्व हिंदी सम्मेलन का सचिवालय मॉरीशस में स्थापित किया गया है ताकि विश्व में कार्यरत हिंदी प्रचार संस्थाओं से बराबर संपर्क-संवाद और सूचनाओं का आदान-प्रदान बना रहे। भारत के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की घोषणा से विश्व हिंदी दिवस पहली बार 2006 में मनाया गया। नार्वे स्थित भारतीय दूतावास ऐसा आयोजन करने वाला पहला दूतावास बना। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर भारत के विभिन्न कार्यालयों, संस्थाओं एवं भारतीय दूतावासों में व्याख्यानमाला, प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन, क्विज एवं भाषण प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज 150 से अधिक देशों में भारतवंशी हैं जहां हिंदी बोली जा रही है। 75 से अधिक देशों के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों एवं स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। वर्ल्ड लैंग्वेज डाटाबेस द्वारा 2022 में प्रकाशित 'एथेनोलॉग' के 25वें संस्करण के अनुसार अंग्रेजी और चीना भाषा के बाद हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली तीसरी भाषा है। दक्षिण अफ्रीका में हिंदी संविधान द्वारा संरक्षित भाषा है।

हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस आयोजन के संदर्भ में पाठक भ्रमित हो सकते हैं। इस संदर्भ में निवेदन है कि 14 सितंबर, 1949 को अनुच्छेद 343 अंतर्गत हिंदी भाषा को संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि के साथ भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की स्मृति हेतु प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम 14 सितंबर, 1953 को हिंदी दिवस मनाया गया। वहीं विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है जो एक अंतरराष्ट्रीय आयोजन है। इस आयोजन की एक थीम निश्चित की जाती है। 2024 की थीम थी 'हिंदी का पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता' जबकि वर्ष 2025 की थीम है - हिंदी : एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। हिंदी के बढ़ते प्रभाव का ही परिणाम है कि 2019 में आबू धाबी ने हिंदी को न्यायालय की तीसरी भाषा के रूप में मान्यता दी है तथा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बहुत सारे हिंदी शब्दों को अपने नवीन संस्करण में स्थान दिया है जो हिंदी के बढ़ते प्रभाव का संकेत है। 1977 में विदेश मंत्री तथा 2002 में प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेई जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने विदेश प्रवास में विभिन्न संसदों, सरकारी कार्यक्रमों तथा भारतीय समुदाय को हिंदी में ही सम्बोधित करते हैं। उल्लेखनीय है कि विदेश में बसे भारतीय मूल के दो करोड़ भारतवंशी हिंदी माध्यम से कार्य संपादित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, स्पेनिश और अरबी को आधिकारिक दर्जा प्राप्त है, बावजूद इसके संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा प्रति सप्ताह महत्वपूर्ण सूचनाओं का एक पत्रक हिंदी में प्रकाशित किया जाता हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, श्रीलंका द्वारा रेडियों पर हिंदी में कार्यक्रम एवं समाचार प्रसारित किये जा रहे हैं।

इंटरनेट के युग में विश्व एक गांव के रूप में उभरा है। परस्पर संवाद के लिए हिंदी एक सहज माध्यम बनी है। कहा जा रहा है की तेजी से बदलते इस संचार युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में केवल 8-10 भाषाएं ही बचेंगी जिसमें हिंदी प्रमुख होगी। आज हिंदी की आवश्यकता संपूर्ण विश्व महसूस कर रहा है क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। इसलिए पूरी दुनिया की बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं व्यापारिक संस्थाएं भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखते हुए अपने कर्मचारियों को हिंदी सीखने को प्रेरित एवं प्रशिक्षित कर रही हैं, साथ ही विज्ञापन की भाषा भी हिंदी दिखाई पड़ने लगी है। हिंदी दिनों दिन समृद्ध हो रही है क्योंकि विभिन्न भाषाओं के जरूरी शब्द हिंदी उदार मन से न केवल स्वीकार कर रही है बल्कि दैनंदिन कार्य-व्यवहार में उपयोग भी कर रही है। आकाशवाणी केन्द्रों एवं टीवी चैनलों के विविध मनोरंजक कार्यक्रमों द्वारा विश्व के अनेक देशों तक हिंदी पहुंच और पसन्द की जा रही है। हिंदी फिल्में भी विदेश में देखी-सराही जा रही हैं। फिजी, गुयाना, सूरीनाम, टोबैगो, ट्रिनिडाड और अरब अमीरात में हिंदी को आधिकारिक रूप से अल्पसंख्यक भाषा का दर्जा प्राप्त है। अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नार्वे, कनाडा आदि अन्यान्य देशों में 25 से अधिक पत्र-पत्रिकाएं हिंदी में निकल रही हैं और हिंदी में रेडियो कार्यक्रम संचालित होते हैं। विश्व हिंदी दिवस के अवसर हम हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का संकल्प ले हिंदी को समृद्ध एवं सुदृढ़ वैश्विक आधार प्रदान करें, यही कामना और अपेक्षा है।

॥ मंदिरम् ॥

08

पावलवन्नम मंदिर, तमिलनाडु

पावलवन्नम मंदिर या पावलवन्ना पेरुमल भगवान विष्णु का मंदिर है जो तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर 108 दिव्य देसमों में से एक है , और इसकी प्रशंसा आलवार संतों पेयाझवार, थिरुमालिसाई आलवार और थिरुमंगई आलवार के भजनों में की गई है, और इस प्रकार इसे नलयिरा दिव्य प्रबंधम रचनाओं में शामिल किया गया है। पावलवन्नम मंदिर या पावलवन्ना पेरुमल यहाँ भगवान विष्णु को दिया गया नाम है, और पावजवल्ली उनकी पत्नी हैं। इस मंदिर में भगवान पावलवन्नम के बारे में कहा जाता है कि वे ऋषि नैमिषारण्य को दिखाई दिए थे। यह कांचीपुरम के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, जहाँ बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। मंदिर का उल्लेख दिव्य प्रबंध में किया गया है, जो 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के आज़वार संतों का एक प्रारंभिक मध्यकालीन तमिल ग्रंथ है। पावलवन्नार पेरुमल भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि पावजवल्ली उनकी पत्नी लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रदेश के कई जिलों में आज कोल्ड-डे का अलर्ट

ठंडी हवाओं ने बढ़ाई तीखी सर्दी, पचमढ़ी में 0.2, भोपाल में 3.6 डिग्री तापमान

भोपाल (नप्र)। जनवरी में कड़ाके की ठंड के दूसरे दौर से पूरा मध्यप्रदेश कांप रहा है। इस साल जनवरी में पहली बार इतनी सर्दी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा रिकॉर्ड 0.2 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं, भोपाल में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। यहां रात का टेम्परेचर 3.6 डिग्री रहा। ऐसा ही मौसम गुरुवार को भी बना रहा। प्रदेश के 9 जिलों में कोल्ड-डे का अलर्ट है। वहीं, सुबह करीब 20 जिलों में कोहरा छाया है। बर्फीली हवा चलने से प्रदेश के शहरों में दिन-रात कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछली 2 रातों से पारा काफी नीचे लुढ़का है। मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख में बर्फ पिघल रही है। जिससे हवा की रफ्तार भी तेज हो गई है। बुधवार को जेट स्ट्रीम हवाओं की रफ्तार 268 किमी प्रतिघंटा रही।

जनवरी में 20 से 22 दिन शीतलहर- मौसम विभाग के अनुसार, जनवरी में प्रदेश का मौसम ठंडा ही रहेगा। 20 से 22 दिन तक शीतलहर चलने का अनुमान है। जनवरी के पहले सप्ताह में भी कड़ाके की ठंड पड़ी थी। अब दूसरा दौर शुरू हुआ है।

अगले 3 दिन ऐसा रहेगा मौसम- 10 जनवरीः गुना, अशोकनगर और श्योपुर में बूंदाबांदी हो सकती है।

11 जनवरीः ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और मऊगंज में कहीं-कहीं बारिश होने का अनुमान है।

12 जनवरीः दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और डिंडौरी में बारिश होने के आसार है।

एमपी के शहर रात के साथ दिन में भी ठंडे- इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा 0.2 डिग्री पहुंच गया। एक ही रात में पचमढ़ी में पारा 6.8 डिग्री तक लुढ़क गया। वहीं, भोपाल में 3.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पिछले 10 साल में यह जनवरी का सबसे कम तापमान है। इंदौर-ग्वालियर में 6-6 डिग्री, उज्जैन में 6 डिग्री और जबलपुर में तापमान 7 डिग्री रहा।

प्रदेश का दूसरा सबसे ठंडा जिला राजगढ़ रहा। यहां तापमान 1.6 डिग्री रहा। मंडला, रायसेन, गुना, उमरिया, मलाजखंड, छिंदवाड़ा, धार, रतलाम में तापमान 6 डिग्री के नीचे ही रहा। सुबह प्रदेश के कई शहरों में मध्यम से घना कोहरा दर्ज किया गया। ग्वालियर-चंबल में दिनभर शीतलहर चली। वहीं, दिन के तापमान में भी गिरावट आई है। दिन में रीवा सबसे ठंडा रहा। यहां पारा 19.5 डिग्री दर्ज किया गया। सीधी में 19.8 डिग्री, मलाजखंड में 20 डिग्री, जबलपुर में 21.2 डिग्री, रायसेन-उमरिया में 21.4 डिग्री, दमोह में 21.5 डिग्री, टीकमगढ़ में 21.8 डिग्री, पचमढ़ी, नौगांव-शिवपुरी में 22 डिग्री, खजुराहो में 22.2 डिग्री, भोपाल-नरसिंहपुर में 22.4 डिग्री, गुना में 23 डिग्री, बैतूल-धार में 23.2 डिग्री, ग्वालियर में 23.3 डिग्री, सागर में 23.7 डिग्री और इंदौर-उज्जैन में 24.5 डिग्री दर्ज किया गया।

11 से 26 जनवरी तक बीजेपी चलाएगी अभियान

कांग्रेस की रैली से पहले भाजपा का संविधान गौरव अभियान 11 से

भोपाल (नप्र)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में कांग्रेस 26 जनवरी को महू में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली करने जा रही है। कांग्रेस की रैली के पहले बीजेपी एक प्रदेश व्यापी अभियान चलाएगी। 11 जनवरी से 26 जनवरी तक भाजपा प्रदेश भर में संविधान गौरव अभियान चलाएगी।

प्रदेश भर में होंगे कार्यक्रम

संविधान गौरव अभियान के तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से लेकर जिला और मंडल स्तर तक के पदाधिकारी, विधायक, सांसद शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों कॉलेज में गोष्ठी, परिचर्चाओं का आयोजन करेंगे। समाज के गणमान्य नागरिकों, बुद्धिजीवियों की संगोष्ठी और चौपाल का आयोजन भी होगा।

वीडी बोले- कांग्रेस का झूठ बेनकाब करें- गुरुवार सुबह बीजेपी की वर्चुअल बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कांग्रेस ने 70 सालों में संविधान में किस तरह से छेड़छाड़ की और बाबा साहब के साथ कांग्रेस ने जिस तरीके का भेदभाव किया उसे जनता के बीच बताने की जरूरत है। संविधान गौरव अभियान के दौरान सभी कार्यकर्ता इन गोष्ठियों में भाग लें और कांग्रेस की बाबा साहब को लेकर फैलाए जा रहे झूठ का मुंह तोड़ जवाब दें। नर्मदापुरम सांसद चौधरी दर्शन सिंह ने बताया-26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। संविधान को कांग्रेस ने तार-तार करने का काम किया है। वहीं, भाजपा ने प्रजातंत्र की रक्षा करते हुए लोकतंत्र की रक्षा का काम किया है। 11 जनवरी से लगातार अभियान चलेगा। मेरा संविधान मेरा गौरव, मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान इस भाव को लेकर जनता के बीच जाएंगे। जो विरोधी भ्रम फैलाने का काम करते हैं। जनता के बीच में उस भ्रम को दूर करने का प्रयास करेंगे।

नेता प्रतिपक्ष बोले- ये अभियान ध्यान भटकाने की कोशिश- बीजेपी के अभियान पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा- बीजेपी हमेशा ध्यान भटकाने की राजनीति करती है और संविधान में जो संशोधन कर रही है तो उन संशोधनों को रोकना चाहिए। आपकी सरकार लोकसभा में ऐसे संशोधन लाएगी, जिनसे जनता प्रभावित होती है।

ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत

- **कैंची छोला में रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा, पुलिस जांच में जुटी**

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कैंची छोला इलाके में बुधवार रात एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। वह रेलवे ट्रैक पार करने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, रविशंकर कुशवाह (38) गली नंबर तीन कैंची छोला निवासी पर्सनल काम से बाहर निकला था और घर के पास स्थित रेलवे ट्रैक को पार करने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव गुरुवार को परिजनों को सौंप दिया गया। रविशंकर के साडू रामबाबू विश्वकर्मा ने बताया कि वह ऑटो चालक था और उसके दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की।

गणतंत्र दिवस पर दिखेगी विरासत से विकास की झलक

भोपाल के रातापानी अभ्यारण्य समेत नवाचार योजनाओं पर तैयार होंगी झांकियां

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में जो झांकियां तैयार की जाएंगी उसमें विरासत से विकास थीम की झलक दिखाई देगी। मोहन सरकार के निर्देश पर इस तरह की झांकियां तैयार करने का काम संबंधित विभागों ने शुरू कर दिया है। विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने विभाग की विरासत से विकास की गाथा वाली झांकी तैयार कराकर समारोह में शामिल कराएंगे।

मोहन सरकार के दूसरे गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार राजधानी के लाल परेड मैदान पर होने वाले मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में विभिन्न विभागों की नवाचार से जुड़ी योजनाओं की झलक दिखेगी। इसको लेकर मोहन सरकार ने तीन महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। संस्कृति विभाग की देखरेख में तैयार हो रही झांकियों के माध्यम से गणतंत्र दिवस समारोह में विरासत और विकास दोनों की ही झलक दिखाई जाएगी।

नवाचार योजनाओं की झलक दिखेगी- गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जो झांकिया सिलेक्ट की जा रही हैं, उनमें विभागों की नवाचार योजनाओं को प्रमुखता से दिखाने पर फोकस किया जा रहा है। इसमें खासतौर पर नारी सशक्तिकरण, स्वरोजगार योजना, रातापानी अभ्यारण्य, गौ संरक्षण और संवर्धन, औद्योगिक निवेश, किसान कल्याण, सांस्कृतिक और अध्यात्मिक अभ्युदय, पर्यटन विकास के नए आयाम, पर्यावरण के लिए नव जागृति, मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्त्रोत समेत शासन की अन्य नीतियों और योजनाओं पर झांकिया तैयार कराई जा रही हैं।

मध्यप्रदेश में प्लास्टिक उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री ने किया प्लास्टिक उद्योग सम्मेलन 'प्लास्टपैक 2025' का शुभारंभ,प्लास्टिक उद्योग से जुड़ी 400 से अधिक कंपनियां और 2 हजार से अधिक प्रदर्शक ले रहे है हिस्सा

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में प्लास्टिक उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं। यह उद्योग का नया क्षेत्र है और इसका बड़ा बाजार है। इस उद्योग में रोजगार की भी बेहतर और बड़े अवसर हैं। प्लास्टिक उद्योग के विकास के लिए इसके दुष्प्रभाव को दूर कर सावधानी रखते हुए आगे बढ़ेंगे। प्लास्टिक के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए रियूज और वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। रियूज और वेस्ट मैनेजमेंट की तकनीक को विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की मदद भी ली जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को इंदौर में प्रारंभ हुए प्लास्टिक उद्योग सम्मेलन प्लास्टपैक 2025 को संबोधित कर रहे थे। यह सम्मेलन 12 जनवरी तक उद्योग मेले के रूप में चलेगा। इसमें प्लास्टिक उद्योग से जुड़ी 400 से अधिक कंपनियां और 2 हजार से अधिक प्रदर्शक

हिस्सा ले रहे हैं। यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के सहयोग से हो रहा है। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, विधायक श्री रमेश मेंदोला तथा श्री मधु वर्मा, महापौर परिषद के सदस्य श्री अभिषेक शर्मा तथा इंडियन प्लास्टपेक फोरम के चेयरमेन श्री सचिन बंसल आदि मौजूद थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्लास्टिक उद्योग के विकास की प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। इस उद्योग के विकास में पूरी मदद दी जाएगी। बदलते दौर में प्लास्टिक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। यह जीवन उपयोगी भी है। प्लास्टिक ने अपनी उपयोगिता कोविड काल में साबित की है। यह जीवन रक्षक के रूप में सामने आया है। कोविड के दौरान पीपीई कीट हो या मॉस्क आदि में प्लास्टिक का उपयोग हुआ है। जीवन में इसकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है। प्लास्टिक के दुष्प्रभाव भी हैं। इन दुष्प्रभावों को दूर करने के प्रयास होंगे। पर्यावरण की चिंता भी रखी जायेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति और नई दिशा दी जा रही है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए रिजनल स्तर पर इन्वेस्टर समिट आयोजित किये जा रहे हैं। इसके बेहतर परिणाम भी मिल रहें हैं। प्रदेश में अब तक 6 रिजनल इन्वेस्टर समिट आयोजित हो चुकी है। इनके माध्यम से चार लाख करोड़ रूपये का निवेश प्रदेश में आया है। इससे लगभग तीन लाख लोगों को रोजगा मिलेगा। उक्त निवेश से प्रदेश में 200 करोड़ रूपये का राजस्व भी प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में गुजरात मॉडल पर तेजी से विकास किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने सम्मेलन में लगाये गये स्टॉलों का अवलोकन भी किया।

जनजातीय कल्याण कार्यक्रम क्रियान्वयन का लक्ष्य अन्त्योदय हो : राज्यपाल

राज्यपाल पटेल ने की विभिन्न विभागों की समीक्षा

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि जनजातीय कल्याण कार्यक्रम क्रियान्वयन में अन्त्योदय का लक्ष्य रहें। जनजातीय समुदाय की सबसे पिछड़ी जनजाति, उसमें सबसे पिछड़े परिवार को हितलाभ देने में प्राथमिकता दी जाए।

राज्यपाल श्री पटेल ने गुरुवार को पशुपालन, उच्च शिक्षा, वन और जनजातीय कार्य विभाग की क्रमिक रुप से राजभवन में समीक्षा की। बैठक में जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री दीपक खांडेकर, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव श्री के.सी. गुप्ता भी मौजूद थे।

राज्यपाल द्वारा जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा- राज्यपाल श्री पटेल ने जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा में कहा कि प्रधानमंत्री की पहल जनमन कार्यक्रम जनजातीय समुदायों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अभूतपूर्व प्रयास है। जनजातीय परिवार को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का दुर्लभ अवसर है। आवश्यकता संवेदनशीलता के साथ लक्ष्य बनाकर समर्पित भाव से कार्य करने की है। उन्होंने कहा कि जनमन के तहत बनी कार्य-योजना के कार्य समय पर पूरे हों और उनकी गुणवत्ता उत्कृष्ट हो।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग की समीक्षा

राज्यपाल श्री पटेल ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य पी.वी.टी.जी. जनजातियों को सतत आजीविका उपलब्ध कराना है। जरूरी है कि योजना में अति गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी जाए। योजना राज्य सरकार के कार्यक्रम के रूप में पृथक से ही संचालित की जाए। किसी अन्य योजना अथवा कार्यक्रम में समावेशन नहीं किया जाए। राज्यपाल को बताया गया कि राजभवन के निर्देशानुसार जनसंख्या के अनुपात में लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। बैगा जनजाति के 30, सहरिया जनजाति के 374 और भारिया जनजाति के 30 हितग्राही परिवारों को 2-2 दुधारू पशुओं से लाभान्वित किया जा रहा है। पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल और प्रमुख सचिव पशुपालन श्री उमाकांत उमराव भी उपस्थित थे।

राज्यपाल द्वारा उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा- राज्यपाल श्री पटेल ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा में जनजाति प्रतिभाओं के टैलेंट पूल के ऑन एवं ऑफ लाइन सम्मेलनों के आयोजनों की जरूरत बताई है। जनजाति कल्याण योजनाओं केन्द्र सरकार के पोर्टल के साथ विभाग को संबद्ध होने के लिए कहा है, जिससे योजनाओं के दोहरे लाभ की समस्या उत्पन्न नहीं हो।

उन्होंने कहा कि जनजातीय आबादी के मान से विभागीय बजट के प्रावधान के संबंध में विचार किया जाना चाहिए। विभाग द्वारा जनजातीय युवाओं की खेल प्रतिभा और अभिरुचि के अनुसार केन्द्र सरकार के खेल प्राधिकरण के साथ समन्वय से किसी एक खेल को चयनित कर प्रोत्साहन का प्रयास समग्रता के साथ किया जाए। उन्होंने जनजातीय पदों के बैकलॉग के संबंध में भी चर्चा की।

वन विभाग के कार्यों की समीक्षा

राज्यपाल श्री पटेल ने वन विभाग की समीक्षा में विभाग के अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष पहल करें। आवश्यकता होने पर मानव संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में विचार किया जाना चाहिए। राज्यपाल को बताया गया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे देने के प्रावधानों को सरलीकृत किया गया है। विभागीय स्तर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार पट्टाधारियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे देने की कार्रवाई प्रचलित है।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने जिला अस्पताल की बेसिन साफ की

शिवपुरी में डिलेवरी के बाद एम्बुलेंस का इंतजार कर रही महिला को घर छुड़वाया

शिवपुरी (नप्र)। मध्यप्रदेश सरकार के उर्जा मंत्री और शिवपुरी के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने (गुरुवार) दोपहर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान अस्पताल में अस्पताल परिसर में कई जगह गंदगी मिली तो वे नाराज हो गए और खुद अपने हाथ से वॉश बेसिन साफ किया। जिला अस्पताल में भ्रमण के दौरान मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को एक प्रसूता एम्बुलेंस के इन्तजार में बैठी मिली। पूछने पर महिला रिंकी वंशकार ने बताया कि मैं मायापुर थाना क्षेत्र के पड़ोरा गांव की रहने वाली हूं। डिलीवरी के लिए मुझे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गर्भ में बच्चे की मौत हो गई थी। एक दिन पहले (बुधवार) शाम के समय मुझे छुट्टी दे दी गई। लेकिन छोड़ने के लिए 108 एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई। रिंकी ने बताया कि कल शाम से ही मैं परिजन के साथ जिला अस्पताल में एम्बुलेंस का इंतजार कर रही हूं।

परिचर्चा

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्री श्री चैतन्य कुमार काश्यप की अध्यक्षता में प्रचलित विभागीय नीतियों पर प्रदेश के प्रमुख उद्योग संगठनों के पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों की परिचर्चा हुई।स

निःशक्तजन विवाह योजना राशि के अधिकार अब जिला कलेक्टर को

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह योजना के तहत हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने 2 लाख रूपये तक की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने के अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदान कर दिये है। प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण सशक्तिकरण श्रीमती सोनाली वायंगणकर ने बताया कि दिव्यांगों को विवाह करने के लिये विभाग द्वारा मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में विवाह करने वाले दम्पती में अगर एक व्यक्ति दिव्यांग होता है तो राज्य सरकार दो लाख रूपये तथा दम्पत्ति में दोनों दिव्यांग होते है तो एक लाख रूपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। इस योजना में हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि आसानी से प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य से राशि स्वीकृति के अधिकार जिला स्तर पर अब कलेक्टर को दिये गये है। कलेक्टर निराश्रित निधि की मूल राशि या ब्याज की राशि से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर सकेंगे।

गौर ने की राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण संबंधी बैठक

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विमुक्त घुमंतू और अर्धघुमंतु कल्याण विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौर ने मंत्रालय में गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण गतिविधियों के संबंध में बैठक ली।

उदयपुर के चिंतन शिविर में शामिल होंगी मंत्री भूरिया

10 से 12 जनवरी के बीच होगा चिंतन शिविर

भोपाल (नप्र)। महिला-बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया राजस्थान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित दूसरे चिंतन शिविर में शामिल होंगी। उदयपुर में 10 से 12 जनवरी के बीच इस चिंतन शिविर में सभी राज्यों की महिला एवं बाल विकास मंत्री मौजूद रहेंगी। मंत्री सुश्री भूरिया शिविर में झाबुआ जिले में किए गये नवाचार कुपोषण मुक्त अभियान के तहत 'मोरी आई' कान्सेज के संबंध में जानकारी साझा करेंगी। झाबुआ जिले में लागू इस नवाचार के सुखद और सकारात्मक परिणाम मिले है।केन्द्रीय महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने झाबुआ में शुरू किए गये नवाचार की सराहना की थी। राजस्थान के उदयपुर में हो रहे चिंतन शिविर में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महिला एवं बाल विकास व समाज कल्याण मंत्रियों के साथ-साथ राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। ये अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्रों, पोषण आहार तथा महिला एवं बाल विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर और राज्यों की जरूरत के अनुसार रोडमैप तैयार करेंगे।

मप्र कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में समिति के अध्यक्ष विधायक राजेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के सदस्यगण सर्वश्री सुरेन्द्र चौधरी, अजीता वाजपेयी पाण्डेय, दिलीप सिंह गुर्जर और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी राजीव सिंह उपस्थित थे। कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ने बताया कि समिति में महत्वपूर्ण विषयों में विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें संगठन में अनुशासनहीनता करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी प्रमुख विषय रहा।

कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने ओपीडी और लैब सेवाओं का किया निरीक्षण

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने अस्पताल की ओपीडी और लैब सेवाओं का गहन निरीक्षण किया। अपने दौरे के दौरान, उन्होंने अस्पताल सेवाओं की कार्यप्रणाली का बारीकी से अवलोकन किया और डॉक्टरों, नर्सों और प्रशासनिक कर्मचारियों सहित अस्पताल के स्टाफ के साथ बातचीत की, ताकि

अस्पताल सेवाओं के सुचारू और कुशल संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। प्रो. सिंह ने सभी रोगियों को समय पर और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने मरीजों से सीधे बातचीत की, उनकी प्रतिक्रियाएँ लीं और उन्हें आश्वस्त किया कि संस्थान स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस निरीक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए, प्रो. सिंह ने कहा, एम्स भोपाल में, हम उच्चतम मानकों की चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नियमित मूल्यांकन हमें सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है, जिससे हमारे मरीजों को कुशल, सहानुभूतिपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण उपचार प्राप्त हो सके।

एम्स में कोरियोनिक विलस सैंपलिंग प्रक्रिया से चिकित्सा में नई दिशा

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में, संस्थान ने एक बार फिर चिकित्सा अनुसंधान, नवाचार और स्वस्थ्य देखभाल के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता को साबित किया है। हाल ही में, एम्स भोपाल के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में पहली कोरियोनिक विलस सैंपलिंग (सीवीएस) प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई है। यह प्रक्रिया डॉ. मनुप्रिया माधवन, विजिटिंग फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट द्वारा की गई।

हाईकोर्ट ने थानों से मंदिर हटाने वाली याचिका की खारिज

कहा- 2009 में दे चुके फैसला, एक ही मुद्दे पर पुनः याचिका क्यों?

एमपी में 1159 थानों में से 800 में मंदिर हैं। ज्यादातर थानों में हनुमान जी के मंदिर हैं

जबलपुर (नप्र)। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के थानों में बने मंदिरों को हटाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। जबलपुर निवासी अधिवक्ता ओपी यादव ने यह याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया था कि पुलिस अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर थानों में अवैध धार्मिक स्थल बना रहे हैं।

चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से जवाब मांगा था।

कोर्ट ने 2009 में इसी विषय पर पहले ही आदेश जारी किया था कि सार्वजनिक संपत्ति पर किसी प्रकार का धार्मिक स्थल नहीं बनाया जा सकता। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इन धार्मिक स्थलों को हटाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि एक ही मुद्दे पर पुनः याचिका क्यों लगाई गई। मामले पर हाईकोर्ट में 4 नवंबर, 19 नवंबर और 16 दिसंबर को भी सुनवाई हुई थी।

इस याचिका पर बार काउंसिल के अधिवक्ता दिनेश अग्रवाल ने भी हस्तक्षेप किया और बताया कि वर्तमान में थानों से मंदिर हटाने वाली याचिका में जो वकील है, वह 2009 की याचिका में याचिकाकर्ता थे, उसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, ऐसी स्थिति में अब याचिकाकर्ता चाहे तो कानूनी उपचार का उपयोग करना चाहे तो कर सकता है। फिलहाल अब मंदिर में बने थाने यथावत रहेंगे।

याचिकाकर्ता बोले- अपनी मर्जी से बना रहे मंदिर, जो अवैध हैं

जबलपुर निवासी अधिवक्ता ओपी यादव ने जबलपुर शहर के सिविल लाइन, लार्डगंज, मदन महल और विजय नगर थानों में बने मंदिरों की तस्वीरें हाईकोर्ट में पेश की थीं। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर अपनी मर्जी से मंदिर बना रहे हैं, जो अवैध हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ हैं।

सीएस और डीजीपी को नोटिस जारी

करीब डेढ़ माह पहले याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ की डिवीजन बेंच ने प्रदेश के मुख्य सचिव (सीएस) अनुराग जैन और डीजीपी को नोटिस देकर जवाब मांगा था। नोटिस गृह विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग को भी दिए गए।

दतिया में निर्माण कार्य रोका गया- दतिया जिले के 25 थानों में से 20 में मंदिर बने हैं। इनमें से 5 मंदिर 100 साल से भी पुराने हैं। दतिया के कोतवाली थाने में नया मंदिर बनाया जा रहा था, लेकिन हाईकोर्ट के नोटिस के बाद निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। सिविल लाइंस थाने में हर शनिवार को बड़े धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मां शारदा के किए दर्शन

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मैहर अल्प प्रवास में मां शारदा देवी के दर्शन किये। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की।

विदिशा के आउटसोर्स लाइन स्टॉफ रामविलास ने सुरक्षा ट्रेनिंग देकर पेश किया अनुकरणीय उदाहरण

भोपाल (नप्र)। एम.पी. ट्रांसको (मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी) के विदिशा ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेन्स उपसंभाग के आउटसोर्स कर्मी श्री रामविलास ने एक अनूठा उदाहरण पेश करते हुये 220 के.व्ही. सब-स्टेशन विदिशा में एम.पी. ट्रांसको के नियमित कर्मियों सहित अन्य आउटसोर्स कर्मियों को ट्रांसमिशन लाइन एवं सबस्टेशनों में सुरक्षित कार्य करने के लिये एक सुरक्षा ट्रेनिंग दी। सामान्यतः एम.पी. ट्रांसको में इस तरह की ट्रेनिंग वरिष्ठ एवं विशेषज्ञ इंजीनियर्स द्वारा दी जाती रही है, परंतु मध्यप्रदेश में यह पहला मौका है जब किसी आउटसोर्स कर्मी ने सुरक्षा संबंधी समस्त प्रक्रियाओं को पहले अच्छे से समझा जाना और फिर पहले स्वयं प्रशिक्षित होकर अन्यों को भी प्रशिक्षित करने का उल्लेखनीय कार्य किया।

विदिशा जिले के स्थानीय निवासी श्री रामविलास ने एम.पी. ट्रांसको के 35 अधिकारी/कर्मचारियों को ट्रांसमिशन लाइन और सब-स्टेशनों में कार्य के दौरान प्रयोग किये जाने वाले सेफ्टी बेल्ट के उपयोग करने के तरीके, इसके बांधने से होने वाली सुरक्षा तथा सेफ्टी बेल्ट बांध कर कार्य करने के दौरान बरती जाने वाली सावधानी के बारे में विस्तारपूवर्क बताया। एक मेंटेनेन्स कर्मी द्वारा दिये गये इस व्यावहारिक ट्रेनिंग से उपस्थित मेंटेनेन्स स्टॉफ का न केवल मनोबल बढ़ा बल्कि सभी ने कार्य के दौरान अनिवार्य रूप से सुरक्षा बेल्ट बांधने की शपथ भी ली।ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने श्री रामविलास के इस प्रयास की सराहना करते हुये इसे अन्यों के लिए अनुकरणीय बताया।

आमजन के प्रति हमेशा आत्मीयता का भाव रखें : राज्यपाल

● राज्यपाल से मिले सशस्त्र सीमा बल के प्रशिक्षु सहायक कमाण्डेंट ● राजभवन में प्रशिक्षुओं ने की सौजन्य भेंट

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि प्रशिक्षु अधिकारी अपने सेवा काल में आम जनों के प्रति हमेशा आत्मीयता का भाव रखे। गरीब, वंचित और निर्दोषों के साथ शालीन व्यवहार करे।ईमानदार, निष्पक्ष और संवेदनशील अधिकारियों को ही आम जनता के बीच विश्वास और भरपूर सम्मान प्राप्त होता है।

राज्यपाल श्री पटेल 29वें बैच के सशस्त्र सीमा बल के प्रशिक्षु सहायक कमाण्डेंट अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर प्रशिक्षु अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। राजभवन के बैक्वेट हॉल में आयोजित सौजन्य भेंट कार्यक्रम में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव श्री के.सी. गुप्ता भी मौजूद रहे।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि आप उन चुनिंदा व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें सशस्त्र सीमा बल का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर देश सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी को आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएँ देने का अवसर मिलेगा। इस लिए जरूरी है कि आपके कार्य, आचरण और मर्यादा में सदैव जनहित प्राथमिकता में रहे। उन्होंने कहा कि आपका प्रत्येक कदम राष्ट्र

की सेवा और जनता के कल्याण की दिशा में होना चाहिए। यही आपकी सफलता और सच्ची सेवा का मापदंड होगा। आपकी प्रतिबद्धता और दक्षता सशस्त्र सीमा बल की गौरवशाली परंपरा को और भी ऊँचाई पर ले जाएगी जो आपके परिवार, समुदाय, बल, और पूरे राष्ट्र के लिए गर्व का विषय होगी।

डिजिटल चुनौतियों के प्रति रहे जागरूक और आमजनों को भी करे - राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि वर्तमान में साइबर अपराध, तस्करों द्वारा नई-नई तकनीकों का उपयोग, और अन्य उभरती चुनौतियाँ आपके सेवा काल में बड़ा दायित्व प्रस्तुत करेगी। सभी अधिकारी डिजिटल युग की समस्याओं जैसे डिजिटल अरेस्ट, हेकिंग आदि के प्रति पहले स्वयं जागरूक और सतर्क रहे, फिर आमजनों को भी अपने स्तर पर जागरूक करने का प्रयास करे।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि एस.एस.बी. ने वर्तमान परिदृश्य में शांति और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, नक्सलवाद और सीमा प्रबंधन की हर चुनौतियों पर अपनी प्रभावशाली भूमिका निभाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्कृष्ट प्रशिक्षण, अद्वितीय कौशल, और दृढ़ संकल्प के आधार पर आप इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करेंगे।

राज्यपाल श्री पटेल का सौजन्य भेंट कार्यक्रम में पौधा भेंट कर स्वागत और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। उन्होंने सभी प्रशिक्षु सहायक कमाण्डेंट का परिचय प्राप्त किया। स्वागत उद्बोधन सशस्त्र सीमा बल अकादमी भोपाल के उप महानिरीक्षक श्री अजीत सिंह राठौर ने दिया। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग से चयनित 29वें बैच सहायक कमाण्डेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षु अधिकारियों की ओर से सुश्री राशि भारद्वाज और श्री आशीष राघव ने अकादमी के प्रशिक्षण अनुभवों को साझा किया। उप कमाण्डेंट श्री सचिन कुमार ने आभार माना।

समाज सेवा प्रकोष्ठ ने की साहित्यिक गोष्ठी, रचनाकारों ने सुनाई वर्तमान की विसंगतियों पर कविताएं

जितना याद करता हूं अतीत को, वर्तमान शर्मसार होने लगता है : कानूनगो

देवास। समाज सेवा प्रकोष्ठ द्वारा नव वर्ष के अवसर पर एक साहित्यिक रचना गोष्ठी का आयोजन किया गया। रचना पाठ गोष्ठी की अध्यक्षता वरिष्ठ रंगकर्मी और व्यंग्यकार श्री नन्द किशोर बर्वे ने की। इस अवसर पर कवि, चिंतक और व्यंग्यकार श्री सुरेश उपाध्याय, वरिष्ठ साहित्यकार श्री ब्रजेश कानूनगो, गीतकार श्री सुरेश रायकवार, लघुकथाकार श्री बी एल तिवारी, कवि श्री त्रिपुरारी लाल शर्मा,श्रीमती आशा वडनेर, श्रीमती अरुणा सराफ, श्री भूषण सराफ तथा श्री श्याम पांडेय ने रचनापाठ किया।

गोष्ठी में रचनाकारों ने एक ओर जहां समाज परक सुमधुर गीत प्रस्तुत किए वहीं यथार्थवादी समकालीन कविताओं का भी प्रभावी पाठ हुआ। श्री सुरेश उपाध्याय ने पढ़ा- घोड़ों की मंडी/ गधों का व्यापार/ हैरत में खच्चर/ तिरस्कृत लाचार।

कवि श्री ब्रजेश कानूनगो ने पेड़ पर लटके किसान के शव को देखकर लिखी रचना त्यागपत्र और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह को श्रद्धांजली

कविता आत्मग्लानि सुनाई। उन्होंने पढ़ा - जितना याद करता हूं अतीत को/वर्तमान शर्मसार होने लगता है/ कल की मौत /घुलती जा रही आज के जीवन में। श्री नंदकिशोर बर्वे ने पट्टेवाले पजामे से श्री फोर्थ पहनने तक शीर्षक व्यंग्य पढ़ते हुए कहा - श्री फोर्थ पतलून याने न तो पूरा उर्ध्वगामी और न ही पूरा अधोगामी। न पूरा वाम पंथी न पूरा दक्षिण पंथी। उन्होंने अपनी एक मालवी व्यंग्य कविता जय जगदीश हरे भी सुनाई। समाज सेवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री आलोक खरे ने कहा कि साहित्यिक गोष्ठी जैसे रचनात्मक कार्यक्रम से इस वर्ष के कार्यक्रमों की शुरुआत से बेहतर और क्या हो सकता था। साल भर होने वाले समाज सेवा, तंगबस्ती के बच्चों के व्यक्तित्व विकास शिविरों में भी रचनात्मक गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाती रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह क्रम अनवरत जारी रहेगा।प्रारम्भ में श्रीमती प्रतिभा बर्वे ने सरस्वती वंदना का सुमधुर गायन किया। साहित्यकारों का स्वागत सचिव श्री सुबोध भोरासकर तथा अन्य सदस्यों द्वारा किया गया। संचालन श्री श्याम पांडेय ने किया।इस अवसर पर सर्वश्री बलराम जाटव, अशोक सिसोदिया,प्रदीप तिवारी, श्री स्वामी,वर्षा पाठक, पुष्पा महादिक,अर्चना सेन, लक्ष्मण पवार, श्री वडनेरे आदि भी उपस्थित थे।

संतोष चौबे और डॉ. जवाहर कर्णावट श्रीलंका आमंत्रित

भोपाल । भारत सरकार,विदेश मंत्रालय के स्वामी विवेकानंद सास्कृतिक केंद्र, कोलंबो द्वारा प्रथम भारत -श्रीलंका हिंदी सम्मेलन का आयोजन कोलंबो में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को किया गया है। इस सम्मेलन में रबींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे और अंतरराष्ट्रीय हिंदी केंद्र के निदेशक डॉक्टर जवाहर कर्णावट को विशेष रूप से आमंत्रित किया है।इस सम्मेलन में श्रीलंका के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं के 400 सेअधिक हिंदी प्राध्यापक, शोध छात्र एवं विद्यार्थियों की भागीदारी रहेगी। सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में चौबे और डॉ. कर्नावट भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों और भाषाई स्थिति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उल्लेखनीय है कि श्रीलंका में 10 विश्वविद्यालयों और 80 से अधिक संस्थानों में हिंदी की पढ़ाई होती है।

समय से पहचान और उचित इलाज से टीबी का पूर्ण उपचार संभव : उप मुख्यमंत्री

*कटनी में निक्षय शिविर में हुए शामिल

*उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, निक्षय मित्रों और संस्थाओं को किया सम्मानित

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिसंबर-2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में मध्यप्रदेश में व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। राज्य के 23 जिलों में 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान संचालित किया जा रहा है। इन जिलों में अब तक 20 लाख मरीजों की जांच पूरी हो चुकी है और उन्हें निःशुल्क उपचार प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीबी पूरी तरह से उपचार योग्य है। समय से पहचान और उचित इलाज से इसका पूर्ण उपचार संभव है। उन्होंने आव्हान किया कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए सभी आगे आएं, आमजन को जागरूक करें, टीबी उन्मूलन में सक्रिय योगदान दें। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ज़िला चिकित्सालय कटनी में निक्षय शिविर में शामिल हुये।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने स्वास्थ्य

कर्मियों से आह्वान किया कि पूर्ण समर्पण से अभियान को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दें। उन्होंने आमजन से स्वास्थ्य कर्मियों को सहयोग प्रदान करने की अपील की है ताकि समाज का सशक्त और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने निक्षय मित्रों की अभियान में सक्रिय सहभागिता के लिये सराहना की और अधिक से अधिक समासेवियों नागरिकों से टीबी मुक्त भारत अभियान में सहभागिता की अपील की। उन्होंने कहा कि टीबी के इलाज के लिए निःशुल्क दवा की व्यवस्था है, परंतु दवा की पूरी खुराक और पौष्टिक आहार का सेवन सुनिश्चित करने के लिए समाज की सहभागिता ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि देश को प्रदेश को टीबी से मुक्त बनाने के लिए हम सभी को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विकसित भारत की संकल्पना में स्वस्थ भारत को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में निरंतर विस्तार कर रही है। उन्नत चिकित्सा सेवाओं को प्रदेश के हर कोने में पहुंचाने के लिये अधोसंरचना विकास के साथ पर्याप्त चिकित्सकीय और सहायक चिकित्सकीय मैनपॉवर की व्यवस्था की जा रही है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने शिविर में टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, नि-क्षय मित्रों और टीबी रोग से मुक्त होकर स्वस्थ जीवन जीने वाले टीबी चैंपियनों को सम्मानित किया। विधायक बड़वारा श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह, कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक श्री अभिजीत कुमार रंजन, सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, निक्षय मित्र, समाजसेवी शामिल हुए।

मध्यप्रदेश शासन

डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

देश का दिल
लिख रहा
**विकास का
नया अध्याय**

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

इन्वेस्ट मध्यप्रदेश

अनंत संभावनाएँ

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट

24 25 फरवरी 2025, भोपाल

समिट की रूपरेखा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कर-कमलों से शुभारंभ

- सेक्टोरल समिट
- थीमेटिक सेमिनार
- एग्जीबिशन एंड एक्सपो
- प्रवासी मध्यप्रदेश

पंजीकरण करने के लिए स्कैन करें।
www.investmp.in

D-11149/24

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी